



नई दिल्ली, बुधवार
19 फरवरी 2025

नेशनल प्रेस टाइम्स



राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

नई दिल्ली। (राष्ट्रीय संस्करण)

वर्ष : 10, अंक : 333

www.nationalpresstimes.com

पृष्ठ : 10

मूल्य : 05 रुपये

RNI No : UPHIN/2015/64579

सीएम योगी बोले

भोजपुरी, अवधी का विरोध कर रहे सपा के लोग, बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादियों का चरित्र दोहरा हो चुका है। ये लोग देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाएगी और जब सरकार आम जनता के बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करती है, तो ये लोग उर्दू थोपने की वकालत करने लगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहती है, जो कर्तई स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को विधानसभा की कार्यवाही में स्थान

देने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन बोलियों को हिंदी की उपभाषाएं मानते हुए सरकार इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार इन भाषाओं के लिए अलग-अलग अकादमियों का गठन कर रही है, ताकि ये समृद्ध हों।

ये हिंदी की बेटियां हैं और इन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए। यह सदन केवल विद्वानों के लिए नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज को यहां स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी का विरोध कर रहे हैं, वे दरअसल उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के विरोधी हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इनका

चरित्र ही दोहरा हो चुका है।

सीएम योगी ने कहा कि ब्रजभाषा इतनी समृद्ध है कि संत सूरदास ने इसी भाषा में अपनी रचनाएं दीं। इसी तरह, संत तुलसीदास जी ने अवधी में रामचरितमानस की रचना की, जो न केवल उत्तर भारत बल्कि प्रवासी भारतीयों के लिए भी संकट काल में संबल बनी। उन्होंने कहा कि जो लोग आज भोजपुरी,

भाषाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तब कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

शेष पेज 2 पर

ममता बनर्जी का विवादित बयान, महाकुंभ को बताया 'मृत्यु कुंभ'; विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर भी बोलीं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ 2025 को 'मृत्यु कुंभ' कहा और उत्तर सरकार में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने विधानसभा में राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के भाषण और विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा।

पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विवादित बयान दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए महाकुंभ 2025 को 'मृत्यु कुंभ' बता दिया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह महाकुंभ सम्मान करती हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान में क्या कहा- बनर्जी ने कहा, 'यह



मृत्यु कुंभ है..मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ, मैं पवित्र गंगा मां का सम्मान करती हूँ। लेकिन इसके लिए कोई योजना नहीं है, कितने शव बरामद हुए हैं ?

अमीरों, वीआईपी लोगों के लिए एक लाख रुपये तक के शिविर पाने की व्यवस्था है।

शेष पेज 2 पर

राज्यपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में गिनाई योगी सरकार की उपलब्धियां बताया कई क्षेत्रों में किया काम

लखनऊ। यूपी बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में योगी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान का वर्णन किया।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब तक डेढ़ करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित की और 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अपग्रेड किए हैं। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंगलवार को सदन के पटल पर अपना अभिभाषण रखते हुए शिक्षा में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, राजकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त व समाज कल्याण विभाग द्वारा



संचालित विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त मदरसों में बच्चों को पाठ्य-पुस्तकें निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि कक्षा 01 से कक्षा 08 तक 1 करोड़ 49 लाख छात्र/ छात्राओं को इस योजना का लाभ मिला। हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की पाठ्य-पुस्तकों के साथ ही दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि की पाठ्य-पुस्तकें भी निःशुल्क उपलब्ध कराई

जा रही हैं। वहीं, पीएम श्री योजना के अन्तर्गत संचालित 1 हजार 565 विद्यालयों में आधुनिक अवस्थापना सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए आदर्श विद्यालय विकसित किए गए हैं।

06 हजार 481 जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण- राज्यपाल ने बताया कि कमजोर वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराते हुए

680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 06 हजार 481 जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण कराया जा चुका है।

छात्र-छात्राओं की यूनीफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी के लिए डीबीटी के माध्यम से 1 हजार 200 रुपये प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में दी जा रही है। इसके अलावा अनुश्रवण को प्रभावी बनाने के लिए परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोग के लिए 02 लाख 10 हजार टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं।

शेष पेज 2 पर

पटना में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया



पटना। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि चार राउंड फायरिंग की गई। इस घटना में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। इमारत के अंदर मौजूद सभी नागरिक सुरक्षित हैं। हम कुछ गुंडों का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो फरार हो गए हैं। स्थिति सामान्य है।

बिहार में पटना के कंकड़बाग इलाके में

अपराधियों ने आज एक घर के बाहर गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस को इलाके की घेराबंदी करनी पड़ी। गोलीबारी के बाद सभी अपराधी पास के एक घर में छिप गये. फायरिंग कंकड़बाग के रामलखन पथ पर दोपहर करीब 2 बजे हुई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले चार बदमाशों को हिरासत में लिया है और कुछ बदमाश भाग गए। पुलिस फरार अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। शेष पेज 2 पर

राहुल गांधी ने नए CEC के चयन पर उठाए सवाल, बताया इसका कारण

नयी दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि ऐसे समय मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन का निर्णय आधी रात को लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लिए गरिमा के प्रतिकूल है, जब चयन समिति की संरचना और प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और 48 घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सोमवार शाम को आयोजित चयन समिति की बैठक के बाद ज्ञानेश कुमार को भारत के नए सीईसी के रूप में नियुक्त किया गया। इस समिति में गृह



मंत्री और राहुल गांधी भी शामिल हैं।

राहुल गांधी ने अपने असहमति नोट की प्रति साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, हूअगले मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने के लिए हुई समिति की बैठक के दौरान मैंने प्रधानमंत्री और गृह

मंत्री को एक असहमति नोट प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है। शेष पेज 2 पर

नई दिल्ली। भारत और कतर ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। कतर के अमीर और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच चर्चा में व्यापार, निवेश और उर्जा क्षेत्रों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार करीब 14 अरब डॉलर का होता है।

कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने मार्च 2015 में आखिरी बार भारत का दौरा किया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में अपना दूसरा कतर का दौरा किया, तो उन्होंने अमीर को भारत का राजकीय दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था। कतर के अमीर के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक



नेता शामिल हैं। आने वाले गणमान्य व्यक्तियों में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) के सचिव (कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा) अरुण कुमार चटर्जी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सुबह

रणनीतिक स्तर तक पहुंचेंगे भारत-कतर संबंध

समझौते पर हस्ताक्षर, उर्जा क्षेत्र में भी मजबूत होगी साझेदारी

हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत-कतर के बीच ऐतिहासिक व्यापार, लोगों के आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की।

संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने के लिए समझौता- मंत्रालय ने आगे बताया कि भारत और कतर ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोनों नेताओं के बीच चर्चा में व्यापार, निवेश और उर्जा प्रमुख विषय थे। आज भारत और कतर के बीच सालाना करीब 14 अरब डॉलर का व्यापार होता है। दोनों पक्ष अगले पांच वर्षों में इसे दोगुना करने का लक्ष्य तय करने पर सहमत हुए हैं।

शेष पेज 2 पर

असम के कामरूप जिले में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो
असम: असम के कामरूप जिले की जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज मंगलवार, 18 फरवरी को कामरूप जिला आयुक्त देव कुमार मिश्र की अध्यक्षता में उत्तरी गुवाहाटी के अभयपुर के कामरूप जिले की पुलिस छावनी में आयोजित की गई। बैठक में कामरूप जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को यथासंभव कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचआईडीसीएल जैसी सड़क निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों की उपस्थिति में व्यापक विचार-विमर्श किया गया। आज बैठक



में जिला आयुक्त देव कुमार मिश्र ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा मानदंडों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर देने के अलावा उन्होंने आवश्यकता विभाग को कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए ताकि किसी भी कारण से राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ढाबों पर अवैध रूप से शराब न बेची जाए। जिला आयुक्त ने आवश्यकता विभाग को उक्त ढाबों पर नियमित छापेमारी करके अवैध रूप से शराब की बिक्री को नियंत्रित करने का

पुष्टि करते हुए ऐसे ढाबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। बैठक में पुलिस और परिवहन विभाग ने बताया कि जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दोनों विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि बैठक में कामरूप जिला पुलिस अधीक्षक रंजन भुइयां, अतिरिक्त जिला आयुक्त प्रणब दत्ता गोस्वामी, रंगिया सम जिला आयुक्त देबाशीष गोस्वामी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपरध), सोमालिन सुभद्रशिनी, उत्तरी गुवाहाटी

राजस्व सर्कल के सर्कल अधिकारी भास्करज्योति कलिता, अधीक्षक अभियंता कामरूप, लोक निर्माण सड़क विभाग मृदुल दास सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख मौजूद थे। बैठक में यातायात कानून उल्लंघनकर्ताओं की पहचान करने में मदद करने के लिए पर्याप्त संख्या में ब्रेथ एनालाइजर की खरीद, जिन इलाकों में सड़क हादसे हुए हैं उस इलाके पर जाकर दुर्घटना के कारण की पहचान आदि सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने दिया बिश्वनाथ जिले के सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बधाई का सौगात

बिश्वनाथ जिला आयुक्त मुनींद्र नाथ नाटे ने किया औपचारिक रूप से इसका वितरण।



असम। असम सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के विभिन्न हिस्सों के पत्रकारों के साथ-साथ आज बिश्वनाथ जिले के पत्रकारों के लिए भी असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा

सरमा द्वारा भेजे गए सद्भावना उपहारों को औपचारिक रूप से बिश्वनाथ जिले के पत्रकारों के बीच वितरित किया गया। इस उद्देश्य के लिए बिश्वनाथ के जिला आयुक्त के सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक विशेष समारोह में जिला आयुक्त मुनींद्र नाथ नाटे ने बिश्वनाथ जिले के सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को औपचारिक रूप से उपहारों के गुलदस्ते सौंपे। जिला आयुक्त मुनीन्द्र नाथ नाटे ने मुख्यमंत्री द्वारा भेजी गई उपहार टोकरी सौंपते हुए पत्रकारों को हर समय उनके समर्थन और सहयोग के लिए

धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। पत्रकारों की ओर से पत्रकार प्रणव ओझा ने भी लंबा भाषण दिया और मुख्यमंत्री को इस तरह के तोहफे के लिए धन्यवाद दिया। जनसंपर्क विभाग की ओर से रंजीत सैकिया द्वारा शुरुआत किए गए कार्यक्रम में अपर जिला आयुक्त हृदय कुमार दास, सहायक आयुक्त एवं प्रभारी जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी पुष्पांकर पाटीर, प्रशासनिक अधिकारी गिरीश हजारीका, जिले के मान्यता प्राप्त पत्रकार, जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी ओर कमाचारी उपस्थित थे।

आप को झटका: सत्येंद्र जैन पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, राष्ट्रपति ने दी गृह मंत्रालय को मंजूरी

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और पर्याप्त सबूतों के आधार पर जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया था। दिल्ली में सत्ता गंवांने के

बाद आज आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आप नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चालने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति दे दी है। ईडी अब राष्ट्रपति की मंजूरी की जानकारी देते



हुए एक नया पूरक आरोपपत्र अदालत में दाखिल करेगा। बता दें कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी थी।

जमानत पर बाहर हैं जैन-गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और पर्याप्त सबूतों के आधार पर जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया था। बता दें कि जांच एजेंसी ने कथित

हवाला लेनदेन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जैन पर मामला दर्ज किया था और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

पेज एक का शेष...

भोजपुरी, अवधी का विरोध कर रहे सपा के लोग, बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं

हर अच्छे कार्य का विरोध करते हैं समाजवादी- सीएम योगी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का स्वभाव ही यह बन चुका है कि वे हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग प्रदेश और देश के हित में किए जाने वाले हर सकारात्मक कदम का विरोध करते हैं। यह नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय ने जब स्थानीय भाषाओं को मान्यता दी तो समाजवादी पार्टी ने इसका भी विरोध किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा का यह दोहरा रवैया जनता को समझ में आ रहा है और उन्हें समाज के सामने एक्सपोज किया जाना चाहिए।

देश को कठमुल्लापन की ले जाना चाहते हैं समाजवादी-सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन भाषाओं को सम्मान दिलाने के लिए भोजपुरी अकादमी, अवधी अकादमी और ब्रज अकादमी की स्थापना की जा रही है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मातृभाषाओं को सहजें और उन्हें आगे बढ़ाएं। विपक्ष का यह विरोध बताता है कि वे न केवल विकास के विरोधी हैं, बल्कि हमारी संस्कृति के भी विरोधी हैं। ये लोग अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वह सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते हैं कि नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको। यानि ये बच्चों की मौलवी बनाना चाहते हैं। देश को कठमुल्लापन की ले जाना चाहते हैं यह नहीं चल सकता है।

देश की करीब आधी आबादी ने लगाई त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत की अनुमानित जनसंख्या 143 करोड़ (1.43 अरब) है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या लगभग 110 करोड़ (1.10 अरब) है। इस तरह अगर स्नानार्थियों की संख्या की तुलना भारत में सनातनियों की संख्या से की जाए तो 50 प्रतिशत लोग अब तक त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं।

यदि देश की कुल जनसंख्या से स्नानार्थियों की तुलना की जाए तो यह 38 प्रतिशत से अधिक बैठता है। यानी देश की कुल जनसंख्या की 38 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुकी है। प्यू रिसर्च 2024 की रिपोर्ट मानें तो पूरी दुनिया में 120 करोड़ (1.2 अरब) आबादी सनातन धर्म को मानने वाली है। इस लिहाज से पूरी दुनिया के 45 प्रतिशत

से ज्यादा सनातनियों ने संगम में डुबकी लगाई है।

योगी की उम्मीदों के पार पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा-मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओत-प्रोत साधु-संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थों का स्नान अब उस शिखर के भी पार पहुंच गया है, जिसकी महाकुंभ से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी कि स्नानार्थियों की संख्या का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। उन्होंने शुरुआत में ही 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई थी।

बता दें कि उनका यह आंकलन बीते 11 फरवरी को ही सच साबित हो गया था। वहीं शुक्रवार (14 फरवरी) को यह संख्या 50 करोड़ के ऊपर पहुंच गई और अब इसने 55 करोड़ का नया शिखर छू लिया है। अभी महाकुंभ के समापन में नौ दिन शेष हैं और एक महत्वपूर्ण स्नान पर्व शेष है। पूरी उम्मीद है कि स्नानार्थियों की यह संख्या 60 करोड़ के ऊपर जा सकती है।

विभिन्न स्नान पर्वों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़-यदि अब तक के कुल स्नानार्थियों की संख्या का विश्लेषण करें तो सर्वाधिक करीब आठ करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया था, जबकि 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान किया था। एक फरवरी और 30 जनवरी को 2-2 करोड़ के पार और पौष पूर्णिमा पर 1.7 करोड़ श्रद्धालुओं ने पुण्य डुबकी लगाई, इसके अलावा वसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई थी। वहीं माघी पूर्णिमा के महत्वपूर्ण स्नान पर्व पर भी दो करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पावन स्नान किया था।

ममता बनर्जी का विवादित बयान, महाकुंभ को बताया 'मृत्यु कुंभ'; विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर भी बोलीं

गरीबों के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, व्यवस्था करना जरूरी है। आपने क्या योजना बनाई है?' राज्यपाल के भाषण पर साधा निशाना-राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के भाषण पर मुख्यमंत्री बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कई राज्यों में डबल-इंजन सरकार है, जहां डबल-इंजन सरकार है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने विपक्ष को (बोलने के लिए) 50 फीसदी समय दिया। उन्होंने सदन के पटल पर कागज फेंके। भाजपा, कांग्रेस और माकपा एक साथ मेरे खिलाफ हैं। उन्होंने मुझे अपना भाषण नहीं देने दिया। 'धर्म के खिलाफ भड़काना

डॉक्टर अभिनव तोमर की नर्सरी में पांच नवजातों की सफल चिकित्सा, माता-पिता ने जताया आभार



सुरेन्द्र मलानिया

बड़ौत: चिकित्सा क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल कायम करते हुए डॉक्टर अभिनव तोमर और उनकी टीम ने दो माताओं के पांच नवजात शिशुओं को नई जिंदगी दी। इनमें से एक मां ने दो जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया, जबकि दूसरी मां ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया। समय से पहले जन्मे



ये सभी नवजात बेहद नाजुक स्थिति में थे, लेकिन डॉक्टर अभिनव तोमर की नर्सरी में लंबे इलाज के बाद आज सभी की स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस मौके पर बच्चों के माता-पिता ने डॉक्टर और उनकी टीम का आभार प्रकट किया। इस विशेष अवसर पर पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय भी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर अभिनव तोमर एवं उनकी टीम की सराहना की। उन्होंने बच्चों के माता-पिता को उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की प्रेरणा दी।

बबीता के जुड़वां बच्चे: बबीता, पत्नी सुधीर कुमार (निवासी सरूरपुर कला), ने पिछले महीने दो जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया था। ये दोनों बच्चियां समय से डेढ़ महीना पहले पैदा हुईं, जिस कारण उनकी शारीरिक स्थिति अत्यंत नाजुक थी। प्रारंभ में, बच्चों को दिल्ली के न्यू नेक्स्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज का खर्च बहुत अधिक था।

बच्चों के माता-पिता ने बताया कि दिल्ली में इलाज की लागत बड़ौत के डॉक्टर अभिनव तोमर की नर्सरी के मुकाबले तीन गुना ज्यादा थी। आर्थिक परेशानियों के



चलते उन्होंने डॉक्टर अभिनव तोमर से संपर्क किया और अपनी स्थिति से अवगत कराया। डॉक्टर अभिनव तोमर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बच्चों को दिल्ली से बड़ौत मंगवाकर इलाज शुरू किया।

दिल्ली के डॉक्टरों ने पहले सदेह जताया कि छोटे शहर में ऐसी उन्नत चिकित्सा संभव नहीं है, लेकिन जब उन्होंने यहां की सुविधाओं को देखा तो वे भी हैरान रह गए।

डॉ अभिनव तोमर ने बताया कि वह जनपद के सभी गांव में जाकर समय-समय पर शिविर लगाकर बच्चों की देखभाल हेतु अभियान चलाते हैं तथा परिजनों को बीमारियों के बारे में अवगत कराते हैं जिससे बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए और वे खुशहाल रहें। पूर्व के वर्षों की तुलना में बागपत जिले में मृत्यु दर में भी काफी गिरावट आई है और अब पहले से अधिक बच्चे स्वस्थ रहते हैं।

एसडी सदर व यंग्स बॉयज टीम ने जीते अपने अपने हॉकी लीग मुकाबले।



: मेरठ। सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर मैदान पर चल रहे 15 वर्षीय 7-ए साइड हॉकी लीग प्रतियोगिता में आज दो हॉकी लीग मुकाबले खेले गए दिन का पहला मुकाबला एसडी सदर एवं 7 स्टार टीम संग खेला गया रोमांचक खेल गए मुकाबले मैच में एसडी सदर टीम ने 7 स्टार टीम को 4-2 से पराजित कर जीत हासिल की।

प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला विजन एकेडमी एवं यंग्स बॉयज टीम संग खेला गया यह मैच यंग्स बॉयज टीम ने 2-0 से जीत लिया।जब कि पराजित टीम कोई गोल नहीं कर पाई।

हॉकी प्रतियोगिता में पहुंचे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष,पूर्व राज्यमंत्री, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चौ नीरपाल सिंह ने विजेता टीम को मेडल ट्रॉफी देकर उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल अनुशासन सिखाता है,खेल भाईचारा सिखाता है।अपना लक्ष्य बनाकर जुनून के साथ हॉकी खेलो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इस दौरान प्रधानाचार्य आदित्य प्रकाश सक्सेना व खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव विजय कौशिक ने कहा कि हमारे इन्हीं बच्चों में एक से एक प्रतिभाएं छुपी हुई हैं,बस उन्हें उबारने की आवश्यकता है। साथ साथ ही विजय कौशिक ने हॉकी कोच जोगेंद्र सिंह की सराहना भी की।

इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग , रविंद्र पाल विहान, हॉकी प्रशिक्षक जोगिंदर सिंह,मोनू सिंह मौजूद रहे।

20 फरवरी से बरेली की यह चीनी मिलें हो जाएंगी बंद चीनी मिलें हो जाएंगी बंद चीनी मिलों पर किसान का 171 करोड़ बकाया

एनपीटी ब्यूरो

बरेली। गन्ने के अभाव में जिले की दो चीनी मिलें बंद हो गईं और दो और मिलें 20 फरवरी तक बंद हो जाएंगी। मार्च के पहले सप्ताह तक सभी मिले बंद होने की संभावना है।

जिले में बहेड़ी की केसर इंटरप्राइजेज, फरीदपुर की द्वारिकेश, मीरगंज की धामपुर, सेमीखेड़ा की सहकारी और नवाबगंज की ओसवाल चीनी मिल हैं। बहेड़ी और नवाबगंज की चीनी मिल ने 15 फरवरी से पराई बंद कर दी है। 20 फरवरी को फरीदपुर और सेमीखेड़ा मिल भी एक साथ बंद होंगी। मीरगंज की चीनी मिल मार्च के पहले सप्ताह में बंद होगी।

ये सभी चीनी मिलें पिछले साल अप्रैल तक चली थीं लेकिन इस बार बारिश और बाढ़ की वजह से गन्ने की फसल को काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा रेड रॉट की बीमारी से भी गन्ने की काफी फसल बर्बाद हो गई।



उपायुक्त गन्ना यशपाल सिंह ने बताया कि पिछले साल चीनी मिलों में 329 लाख क्विंटल गन्ने की पराई हुई थी। इस बार सिर्फ दो सौ लाख क्विंटल पराई का अनुमान है।

तीन मिलों पर 171 करोड़ का बकाया

फरीदपुर और मीरगंज की चीनी मिल किसानों का शत प्रतिशत भुगतान कर चुकी हैं लेकिन सेमीखेड़ा चीनी मिल पर किसानों का 14.43 करोड़ और नवाबगंज पर 32.26 करोड़ का बकाया है। सर्वाधिक 150 करोड़ रुपये का बकाया बहेड़ी मिल पर चल रहा है। उपायुक्त गन्ना यशपाल सिंह ने बताया कि बकाया भुगतान को लेकर तीन मिलों को नोटिस जारी किया जा रहा है।

बार एसोसिएशन शाहबाद की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न

उत्तर प्रदेश रामपुर शाहबाद तहसील सभागार शाहबाद में मंगलवार को बार एसोसिएशन शाहाबाद की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार राकेश कुमार चंद्र तथा विशिष्ट अतिथि नायब तहसीलदार हरीश जोशी व नायब तहसीलदार विश्वास दीक्षित रहे । चुनाव अधिकारी तारिक खा ने बार एसोसिएशन की नव निर्वाचित कार्यकारिणी में सबसे पहले नव निर्वाचित अध्यक्ष तकरीर उर रहमान को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उसके बाद महासचिव आनोद शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुहैल खा, कनिष्क उपाध्यक्ष मारूफ अली, कोषाध्यक्ष रनवीर सिंह, संयुक्त सचिव प्रशासन दिनेश पाल, प्रवक्ता निसारुद्दीन, मीडिया प्रभारी कमल वीर सक्सेना, संयुक्त सचिव मनोज भारती, पुस्तकालय सचिव सत्यवीर सिंह को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन यूथ बार एसोसिएशन के महासचिव वसीम खा एडवोकेट ने किया। शपथ ग्रहण के दौरान ऐल्डर कमेटी के चेयरमैन, अमर सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष मासूम मियां, पूर्व अध्यक्ष रामोतार सिंह एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता अशफाक अहमद, वरिष्ठ अधिवक्ता माथुरी सक्सेना, जसवंत सिंह एडवोकेट, छत्रपाल सिंह एडवोकेट, सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, रेहान खा एडवोकेट,शैजान खा एडवोकेट, विवेक पांडे एडवोकेट, शामिल रहे अंत में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तकरीर उर रहमान ने सभी का आभार व्यक्त किया।

नगर पंचायत शाहाबाद में बोर्ड की बैठक का आयोजन

उत्तर प्रदेश रामपुर शाहबाद। आखिरकार कई बार टलने के बाद नगर पंचायत कार्यालय में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता चेयरपर्सन सुमबुल नाज ने की। बैठक में नगर में होने वाले विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कई सभासदों ने अपने अपने वाडों में विकास कार्य कराए जाने का प्रस्ताव रखा तो कुछ सभासदों ने नगर पंचायत कर्मियों पर सभासदों की अनदेखी का आरोप लगाया।कई बार टलने के बाद मंगलवार को नगर पंचायत में बोर्ड की बैठक का आयोजित हुआ बैठक में सभी सभासदों ने अपने अपने वाडों में सड़क निर्माण, नाली मरम्मत व नालियों पर जाल डलवाने के प्रस्ताव रखे। नगर के बीचों बीच तहसील के मैदान में पार्क बनाने को लेकर ईओ ने एसडीएम हिमांशु उपाध्याय से जमीन नगर पंचायत को हस्तांतरित किया जाने की मांग की। वही बैठक में नगर पंचायत की आय बढ़ाए जाने को लेकर भी मंथन किया गया। बैठक के दौरान सभासद शराफत हुसैन ने शाहबाद नगर में पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब की व्यवस्था कराए जाने की मांग की। बैठक में एसडीएम हिमांशु उपाध्याय, ईओ पुष्पेंद्र राठौर, चेयरमैन पति वसीम खा, बीजेपी नेता सुरेश बाबू गुप्ता, सभासद पति सदाकत खा, शराफत हुसैन, इकरार खा, नाजिया परवीन, तालिब मलिक, अनूप सिंह, श्रीराम, लिपिक नावेद मिया, वीर सिंह, मुजीब मियां, कंप्यूटर ऑपरेटर रेहान खा, इकरार खा, अरशद,विकास आदि रहे।

सड़क हादसे में बाइक सवार घायल

उत्तर प्रदेश रामपुर शाहबाद। बाइक पर सवार होकर दवाई देने शाहबाद आ रहे भीतरगांव के विपिन कुमार और उनकी पत्नी सड़क हादसे में घायल हो गए। जिनको उपचार के लिए नगर के प्राइवेट चिकित्सक के यहां भेजा गया। मंगलवार को शाहबाद के भीतरगांव निवासी विपिन कुमार अपनी पत्नी को नगर के नवजीवन अस्पताल से दवाई दिलवाने बाइक पर लेकर जा रहे थे कि रास्ते में बाइक सवार ने उनको टक्कर मार दी जिसमें दोनों पति पत्नी घायल हो गए।

शिक्षामित्रों का ही भविष्य खराब,वेतन से घर चलाना हुआ बहुत मुश्किल

एनपीटी ब्यूरो

बरेली। बहेड़ी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य संभालने में जुटे शिक्षा मित्र आज भी उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं। मजदूरों से भी कम में बच्चों को तालीम देने वाले शिक्षामित्र महज 10 हजार रुपये महीने की नौकरी कर मजदूरों से भी कम में बच्चों को तालीम दे रहे हैं। समायोजन से कुछ उम्मीद जागी थी जो कि रद्द होने पर फिर वही हालत हो गई। बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षामित्र लगाए गए थे शिक्षकों के बराबर काम कर रहे शिक्षामित्रों को इस समय मात्र 10 हजार रुपए मानदेय के रूप में मिल रहे हैं। जबकि आज के समय मे एक मजदूर 400 से 500 रुपए मजदूरी ले रहे हैं। इस हिसाब से उनके 12 से 15 हजार रुपये महीने की आमदनी बनती है। जबकि उनको एक माह में मात्र 10 हजार मिलते है। इतने कम रुपयों में घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है।

आईके कलेक्शन और हल्द्वानी क्रिकेटर्स ने जीत से किया आगाज

बरेली ने मेरठ को 6 विकेट से हराया,शिव राठी मैन आफ द मैच

एनपीटी ब्यूरो

बरेली। एसआरएमएस इंजीनियरिंग कालेज में मंगलवार को श्रीराम मूर्ति मेमोरियल टी- 20 प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट में आईके कलेक्शन बरेली ने जस क्रिकेट एकेडमी मेरठ को 6 विकेट और हल्द्वानी क्रिकेटर्स ने ओएसिस क्रिकेट एकेडमी को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट का आगाज किया। आईके कलेक्शन बरेली की ओर 28 गेंदों



पर 2 छक्के और 6 चौके लगा कर 47 रन बनाने वाले शिवकुमार राठी को मैन आफ द मैच चुना गया।

दूसरे मैच में 34 रन देकर 3 विकेट लेने वाले हल्द्वानी क्रिकेटर्स के गेंदबाज सूरज सतपाल मैन आफ द मैच रहे।



एनपीटी ब्यूरो

बरेली। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में शाही के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें पीलीभीत के मशहूर कव्वाल सईम (55 साल) और अकरम(32 साल) की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में अरशद कव्वाल समेत उनकी टीम के पांच सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

अलीगढ़ से लौट रहे थे कलाकार

अरशद कव्वाल, जिन्हें अरशद काम्बली के नाम से जाना जाता है, पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र के गहलुईया गांव के निवासी हैं। वे अलीगढ़ में एक कव्वाली कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के बाद अपने गांव लौट रहे थे। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में धौरेरा गांव के पास उनकी इनोवा गाड़ी टनकपुर डिपो की रोडवेज बस से टकरा गई। बस टनकपुर से बरेली की ओर आ रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में सईम कव्वाल और उनके सहयोगी अकरम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अरशद काम्बली, वहीद बेग, जावेद और शोहरत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नवाबगंज पुलिस ने इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि बाकी घायलों का इलाज जारी है।

बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशासन सख्त संजय कम्प्युनिटी हाल में हुई बैठक

एनपीटी ब्यूरो

बरेली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जोनल, सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में मंगलवार को संजय कम्प्यूनिटी हॉल में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभी केंद्र व्यवस्थापकों को नकलमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही परीक्षार्थियों के लिए सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए गए।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष 125 परीक्षा केंद्रों पर कुल 99,436 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने



केंद्र व्यवस्थापकों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की है। ये अधिकारी परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे और सचल दलों के रूप में परीक्षा की व्यवस्था का आकलन भी करेंगे।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्देश दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। साथ ही, बिजली, पेयजल और शौचालय की सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। डीआईओएस अजीत कुमार को निर्देशित किया गया

कि परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएं।

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, एसएसपी अनुराग आर्य, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, एसपी सिटी मानुष पारिक, अपर नगर मजिस्ट्रेट, डीआईओएस, सभी केंद्र व्यवस्थापक, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। प्रशासन की सख्ती से यह स्पष्ट है कि इस बार बोर्ड परीक्षा पूरी पारदर्शिता और सख्त निगरानी में कराई जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो और छात्रों को एक निष्पक्ष परीक्षा माहौल मिल सके।

संपादकीय

मुफ्त की कल्याणकारी योजनाएं स्वावलंबन दें

दिल्ली हादसे की जवाबदेही तय हो

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भयावह भगदड़ में जिन 18 लोगों की जान गई, उसे महज दुर्घटना नहीं कहा जा सकता। सही मायने में यह योजना, दूरदर्शिता और जवाबदेही की विफलता थी। जैसा कि पहले से पता था कि रोज हजारों तीर्थयात्री प्रयागराज महाकुंभ के लिये ट्रेनों में चढ़ने के लिये उमड़ रहे थे, अधिकारी उस भारी भीड़ का अनुमान लगाने और उसे प्रबंधित करने में विफल रहे। जिसके चलते यह दुखद हादसा घटित हुआ। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल समेत कई विपक्षी नेताओं ने रेल मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग है। उनका कहना है कि यात्रियों की अप्रत्याशित संख्या में वृद्धि को देखते हुए भीड़ नियंत्रण के लिये उपाय करने में सरकार विफल रही है, जो एक गंभीर चूक है। निस्संदेह, महाकुंभ पहली बार नहीं हो रहा है। रेलवे यातायात संचालन में इसके पैमाने और प्रभाव का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद इस त्रासदी का सामने आना कई सवालों को जन्म देता है। सवाल मृतकों व घायलों को दिये जाने वाले मुआवजे को लेकर भी है। जबकि सामान्य दिनों में वर्ष 2023 की मुआवजा निर्देशिका में निर्धारित मुआवजा राशि में बड़ा अंतर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार प्रणालीगत मुद्दों को ठीक करने के बजाय नकद भुगतान बढ़ाकर तंत्र की साख को हुई क्षति की पूर्ति का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि विपक्षी दल रेलमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हादसे की सूचना की लीपापोती को लेकर भी सवाल उठे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे रेल हादसों के वक्त रेलमंत्री के रूप में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री और नीतीश आदि ने अपने पद से त्यागपत्र दिए थे। दरअसल, इस्तीफे से परे रेलवे में प्रणालीगत सुधार की भी आवश्यकता है। भारतीय रेलवे को अपने भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल में सुधार करने की जरूरत है। खासकर धार्मिक पर्वों और त्योहार की भीड़ के दौरान अतिरिक्त सावधानी की जरूरत महसूस की जाती है। सही मायनों में दिल्ली समेत तमाम रेलवे स्टेशनों में तीर्थयात्रियों की अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए टिकटों के वितरण और नई ट्रेनों के संचालन को लेकर जिस संवेदनशील प्रशासन की जरूरत थी, वह नजर नहीं आया। ट्रेनों के आने के समय और उनके स्थगित होने पर कारगर वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत थी,वह नजर नहीं आई। दिल्ली हादसे के बारे में कहा जा रहा है कि एक नाम की दो ट्रेनों को लेकर मची भगदड़ हादसे की वजह बनी। एक अनुमान के अनुसार रेलवे प्रयागराज जाने वाले यंत्रियों के लिए हर घंटे डेढ़ हजार सामान्य टिकट जारी कर रहा था। जिसके चलते प्लेटफॉर्म पर तिल धरने की जगह नजर नहीं आ रही थी। निश्चित जगह में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने तथा सीमित मात्रा में टिकट जारी करने की जरूरत थी। पैदल यात्रियों के लिये बने ओवरब्रिज पर लोग पहले ही बैठे थे और नई ट्रेन के आने की घोषणा से मची भगदड़ में कुछ लोग गिरे तो अन्य कई लोग गिरते गए, और दुखद हादसा हो गया। अनुमान लगाना चाहिए था कि सप्ताहांत में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, उसी हिसाब से चौकस सुरक्षा तथा ट्रेनों का संचालन व टिकट वितरण किया जाना चाहिए। हाल के दिनों में तीर्थ यात्रियों के रेल में असुरक्षित सफर करने के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार आ रहे थे। यहां तक कि कंफर्म टिकट वाले यात्री भी ट्रेनों में जगह नहीं पा रहे थे। आरक्षित डिब्बों में घुसने के लिये टकराव तक देखा जा रहा था। रेलवे को सुनिश्चित करना चाहिए था कि सफर के लिये यात्री अपनी जान को जोखिम में न डालें। यात्रियों के स्तर पर भी जिम्मेदार व अनुशासित व्यवहार होना चाहिए था। तीर्थयात्रियों में जो संयम व धैर्य होना चाहिए, वह भी अव्यवस्था के चलते चूकता नजर आया है। सही मायनों में तीर्थयात्री यदि अपनी सुरक्षा के प्रति गंभीर रहें तो ऐसे हादसे टाले जा सकते हैं। दरअसल, भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में भीड़ प्रबंधन के वैज्ञानिक तौर-तरीके अपनाये जाने की जरूरत है। मुद्रौभर पुलिसकर्मियों के सहारे भीड़ नियंत्रण संभव नहीं है। बहरहाल, हादसे की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

पहले प्रकार वाले

सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय होते हैं-सब्सिडीज, मूल्य कटौती, नई कल्याणकारी योजनाएं जो आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले, सुविधाजनक समय पर लागू किए जाते हैं। दूसरी श्रेणी वाले वह हैं, जो पार्टी के घोषणापत्रों के माध्यम से पेश किए जाते हैं- राजकोषीय

परिणामों की परवाह किए बिना बड़े-बड़े वादे। चाहे इसके लिए मुफ्त का भोजन, परिवहन, खातों में नकदी का वादा किया जाए, घोषणापत्र चुनाव आयोग की जांच को आकर्षित नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक मामले में फैसला सुनाया था कि ऐसे वादे जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं कहे जा सकते, मले ही वे निर्विवाद रूप से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों की जड़ें हिलाने वाले हैं।

हरेक चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में जनकल्याण के नाम पर लोकलुभावन घोषणाएं करने की होड़ मचती है। मतदाताओं को मुफ्त चीजों के लालच देकर प्रभावित करने की कोशिशें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी अहम है कि यह प्रवृत्ति श्रम से बचने और निर्भरता को बढ़ाती है। दरअसल, कल्याण कार्यक्रम नागरिकों का अधिकार हैं लेकिन इनकी रूपरेखा ऐसी हो कि ये लोगों को सशक्त बनाएं।

चुनावी मौसम में, भारतीय मतदाता पर विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से वादों की झड़ी लग जाती है। राजनेताओं को अचानक आम आदमी और उसको सता रही चिंताओं की याद आने लगती है। शहरी गरीब, बेरोजगार युवा, अल्पसंख्यक, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली जनता और आदिवासी झू जिनहें पांच सालों में अधिकतर समय उपेक्षित रखा जाता है-अचानक महत्वपूर्ण होकर, भावुक चर्चाओं के केंद्र में आ जाते हैं। यह एक भव्य तमाशा है, वादों का एक ऐसा नाटक, जिसमें नकदी के अलावा मुफ्त बिजली, भोजन और टीवी, साइकिल और लैपटॉप जैसे भौतिक साधन राजनीतिक मनुहार का माध्यम बन जाते हैं।

हाल के दिनों में, हमारे राजनीतिक शब्दकोश में एक नया शब्द शामिल हुआ है : रेवड़ी संस्कृति। प्रधानमंत्री द्वारा मुफ्त की इस तथाकथित संस्कृति की आलोचना ने एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें कल्याणकारी उपायों की वैधता पर सवाल उठाते हुए पूछा जा रहा है कि क्या ये व्यवहार्य हैं या सिर्फ उदारता के वेष में राजकोषीय गैर-जिम्मेदाराना कृत्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अब इस मामले में दखलअंदाजी करते हुए चिंता व्यक्त की है कि अत्यधिक अनुदान लोगों को निष्क्रिय बना रहे हैं।

हाल ही में एक खंडपीठ ने टिप्पणी की कि मुफ्त का राशन लोगों को काम से बचने वाला बना सकता है, और ऐसी नीतियां एक परजीवी वर्ग पैदा कर सकती



हैं। हाल ही में संपन्न दिल्ली चुनावों में, सभी प्रमुख दलों ने मुफ्त उपहार देने में एक-दूसरे के साथ होड़ लगाई थीं झू महिलाओं और युवाओं को मासिक नकद सब्सिडी के अलावा मुफ्त बिजली, पानी, यात्रा, चिकित्सा-उपचार और शिक्षा इत्यादि। कोई आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है,विचार करने लायक है।

बहस का सार व्यापक है : क्या ये मुफ्त चीजें गरीबों के कल्याण के लिए जरूरी हैं या चुनावी लाभ पाने को सियासी दलों की जरूरत भर हैं? एक और मुद्दा : अगर वादा गरीबों के लिए हो, तो इसे मुफ्त रेवड़ी ठहराया जाता है, और जब अमीरों के लिए हो, तो प्रोत्साहन बताया जाता है। इस बहस में, अर्थव्यवस्था पर ध्यान कहीं पीछे छूट जाता है। भारत में मुफ्त तोहफे मोटे तौर पर दो श्रेणियों में आते हैं : वह जो चुनाव घोषणा से पहले दिए जाते हैं या वे जिनका वादा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किया जाता है।

पहले प्रकार वाले सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय होते हैं-सब्सिडीज, मूल्य कटौती, नई कल्याणकारी योजनाएं जो आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले, सुविधाजनक समय पर लागू किए जाते हैं। दूसरी श्रेणी वाले वह हैं, जो पार्टी के घोषणापत्रों के माध्यम से पेश किए जाते हैं- राजकोषीय परिणामों की परवाह किए बिना बड़े-बड़े वादे। चाहे इसके लिए मुफ्त का भोजन, परिवहन, खातों में नकदी का वादा किया जाए, घोषणापत्र चुनाव आयोग की जांच को आकर्षित नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक मामले

में फैसला सुनाया था कि ऐसे वादे जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं कहे जा सकते, भले ही वे निर्विवाद रूप से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों की जड़ें हिलाने वाले हों। अदालत ने चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के परामर्श से दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। ये निर्देश वास्तव में जवाबदेह चुनाव प्रचार को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए 2013 में जारी किए गए थे कि घोषणापत्रों में किए गए वादे यथार्थवादी हों और मतदाताओं को अनुचित प्रभावित न करें। हालांकि, जो हम देखते हैं वह उल्लंघन है, यहां तक कि लाखों करोड़ रु. बांटे जाते हैं। यह मतदाताओं को रिश्वत नहीं, तो और क्या है? और यह पैसा आता कहाँ से है? जाहिर है आपकी और मेरी जेब से। राजनेता हमारी जेबें खाली कर चुनाव जीतते हैं!

मुफ्त की रेवड़ियों पर बहस में दोगलापन साफ दिखता है। जब प्रावधान गरीबों के लिए होंझू जैसे राशन योजना, मुफ्त बिजली, सामाजिक कल्याण लाभ झू इनको रेवड़ी बता प्रचारित किया जाता है, जबकि कॉर्पोरेट अभिजात्य वर्ग को बहुत बड़े पैमाने पर दी टैक्स कटौती को राष्ट्र की प्रगति के लिए जरूरी वित्तीय प्रोत्साहन बताया जाता है। आंकड़े इस तर्क का समर्थन करते हैं। वर्ष 2019 में, सरकार ने घरेलू निमाताओं के लिए कॉर्पोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत और नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 25 से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया था,इस कदम से सरकारी खजाने को 1.5 लाख करोड़ रु. का नुकसान हुआ, जिससे राजकोषीय

घाटा काफी बढ़ा। यह निर्णय 36 घंटों में क्रियान्वित भी कर दिया गया,जोकि मंत्रिमंडल में रखे बिना विशेषाधिकार प्रावधान के जरिये लागू किया गया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट से खुलासा होता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान, जहां गरीबी बढ़ी और बेरोजगारी 15 प्रतिशत जैसे उच्च स्तर पर पहुंच गई वहीं भारत में अरबपतियों की संख्या में 39 प्रतिशत वृद्धि हुई। 10 सबसे अमीर भारतीयों ने इस दौरान जितना मुनाफा बनाया, वह 25 वर्षों तक भारत के प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के लिए पर्याप्त धन जितना है। यह शाश्वत विरोधाभास है। जब सरकार अरबपतियों को कर-लाभ देती, तो यह आर्थिक सुधार के नाम पर होता है। लेकिन जब राहत गरीबों को प्रदान करनी हो तो इसे राजकोषीय गैर-जिम्मेदारी करार दिया जाता है।

मुफ्त चीजों से निर्भरता बढ़ने के बारे में शीर्ष अदालत की हालिया टिप्पणी इस बहस में एक और गंभीर आयाम जोड़ती है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत को लेकर चिंता यह जताई जा रही है कि मुफ्त राशन और कल्याण योजनाएं श्रम करने को हतोत्साहित कर रही हैं। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने टिप्पणी की कि महाराष्ट्र में किसानों को खेत मजदूर मिलने में मुश्किल आ रही है क्योंकि वे दिहाड़ी की बजाय मुफ्त राशन पर निर्भर रहने को तर्जिह देने लगे हैं। जब से मनरेगा योजना विभिन्न रूपों में शुरू हुई है, इस तंगी का असर पंजाब में विशेष रूप से नजर आ रहा है। इससे इस तर्क को बल मिलता है कि कल्याणकारी उपायों की रूपरेखा ऐसी हो कि लोग सशक्त बनें न कि

स्थायी निर्भरता पैदा करने वाली।

निर्भरता बनने के पीछे असल दोषी किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्थाई रोजगार अवसरों की कमी है, न कि कल्याणकारी कार्यक्रम। अगर लोगों के पास सुरक्षित, अच्छे वेतन वाली नौकरियां हों, तो वे दान के रूप में मिलने वाले मुफ्त के अनाज पर निर्भर नहीं होंगे।

कल्याण एक सहायक सीढ़ी बने न कि निठल्ला बनाने वाला प्रश्न। यह विदंबना है कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दर्भ भरने वाला देश 80 करोड़ से अधिक लोगों को बतौर दान मुफ्त राशन दे रहा है- जो इसकी आबादी का लगभग 60 प्रतिशत है। सवाल, क्या गरीब मुफ्त चीजों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, खासकर जब सभी पार्टियां एक जैसे वादे करती हों?

ऐतिहासिक रूप से, हमने मुफ्त चीजों/कल्याणकारी योजनाओं के कई फायदे देखे हैं। जब तत्कालीन सीएम एनटी रामाराव ने आंध्र प्रदेश में एक रुपये प्रति किलो चावल योजना शुरू की, तो उनका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन इसका नतीजा हुआ कि भुखमरी से मौतें अतीत की बात हो गई। नीतीश कुमार द्वारा स्कूली छात्राओं को मुफ्त साइकिलें देने से बिहार में लड़कियों की स्कूलों में हाजिरी और पढ़ाई जारी रखने की दर में वृद्धि हुई। रोजगार गारंटी योजनाओं ने लाखों लोगों को आय सुरक्षा प्रदान की है, भले ही इसने शहरी अभिजात्य वर्ग के लिए घरेलू नौकरों की कमी पैदा कर दी हो।

भारत में बहस इसको लेकर नहीं होनी चाहिए कि हमें कल्याण योजनाओं की आवश्यकता है या नहीं, बल्कि यह यकीनी बनाने के बारे में हो कि इनकी रूपरेखा सही ढंग की और टिकाऊ हो। मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर तोहफे या रियायतें नहीं। वे लोकतंत्र में नागरिक का हक हैं। रेवड़ियों की बजाय, हमें अधिकारों और स्वतंत्रताओं के बारे में बात करनी चाहिए।

अपने एआई इकोसिस्टम को मजबूत करें, भारत के लिए मौका

चीन के पास पहले से ही एक एडवांस साइबर युद्ध सिस्टम है। चीन अपनी डीपसीक वाली एआई टेक्नोलॉजी की मदद से हैकिंग टूल्स से भारत के रक्षा ढांचे, परमाणु सुविधाओं और फाइनैशियल सिस्टम को भी निशाना बना सकता है।

पिछले दिनों चीन के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डीपसीक आर-1 ने आते ही अमेरिका सहित पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। डीपसीक ने अमेरिका के एआई वर्चस्व को तोड़ते हुए एनवीडिया सहित कई अमेरिकी टेक कंपनियों के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए। चीन के एक छोटे से स्टार्टअप ने काफी कम खर्च में इतना शक्तिशाली एआई मॉडल बनाया है, जिसके बारे में दुनियाभर के एआई एक्सपर्ट सोच ही नहीं सकते थे कि चीन भी ऐसा कर सकता है। अब इस एआई ने पूरी दुनिया के टेक महारथियों को हिलाकर रख दिया है।

चाइनीज स्टार्टअप कंपनी ने एक एआई चैट मॉडल, डीपसीक आर -1 पेश किया। इस चाइनीज एआई मॉडल ने एआई एफिसिएंसी, लागत में कमी और स्केलेबिलिटी में शानदार सफलता प्राप्त की है। चीनी कंपनी डीपसीक ने इन खर्चों में 94 प्रतिशत की कटौती की और सिर्फ 6 मिलियन डॉलर के ट्रेनिंग खर्च के साथ एक पॉवरफुल एआई मॉडल बना लिया। एआई मॉडल को बनाने के लिए खर्च को 94 प्रतिशत तक कम करना पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली बात है। डीपसीक ने इसके लिए कई क्रांतिकारी तकनीकों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए, ओपन एआई 32-बिट फ्लोटिंग प्वाइंट्स का उपयोग करता है, जिसमें एक संख्या को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स मेमोरी की आवश्यकता होती है। डीपसीक एआई मॉडल 8-बिट फ्लोटिंग प्वाइंट्स का उपयोग करता है, जिसमें एक संख्या को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स मेमोरी की आवश्यकता होती है। डीपसीक एआई मॉडल 8-बिट फ्लोटिंग प्वाइंट्स का उपयोग करता है, जिससे इसकी मेमोरी की जरूरतें कम हो जाती हैं। इसे सिर्फ 1 बाइट मेमोरी की



आवश्यकता होती है।

दुनिया की शीर्ष कंपनियां आमतौर पर अपने चैटबॉट को सुपरकंप्यूटर से प्रशिक्षित करती हैं, जिसमें 16,000 या उससे ज्यादा चिप्स का इस्तेमाल होता है। डीपसीक के इंजीनियरों ने कहा कि उन्हें सिर्फ 2,000 एनवीडिया चिप्स की जरूरत थी। दुनियाभर के ज्यादातर एआई मॉडल्स एक बार में एक ही शब्द को पढ़ते हैं और प्रोसेस करते हैं, लेकिन डीपसीक एक बार में पूरे वाक्य को पढ़ सकता है और प्रोसेस कर सकता है, जिससे प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो जाता है। चैट जीपीटी-4 को एक जवाब देने में दो सेकंड लगते हैं, जबकि डीपसीक के लिए दावा किया गया है कि यह 90 प्रतिशत सटीकता के साथ एक सेकंड में जवाब दे सकता है।

दरअसल, एआई मॉडल ट्रेनिंग साइकिल के दौरान अरबों शब्दों को प्रोसेस करते हैं। ऐसे में प्रोसेसिंग टाइम

को कम करना, इस एआई कंपनी के लिए बड़ी सफलता है। ओपन एआई का जीपीटी-4 हर कैल्कुलेशन के दौरान 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स को एक्टिव रखता है। वहीं, डीपसीक एक एडवांस एल्गोरिथ्म का उपयोग कर-के सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे को एक्टिव करता है। इससे एक समय में सिर्फ 37 बिलियन सक्रिय पैरामीटर्स होते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि ओपन एआई की तुलना में डीपसीक के एआई मॉडल्स में किसी ब्वेरी के प्रति कैल्कुलेशंस की संख्या काफी कम हो जाती है। यह मॉडल इतनी अच्छी तरह से काम करता है कि टेस्ला के पूर्व एआई निदेशक आंद्रेज करैपैथी ने कहा कि डीपसीक ने कम बजट में एक एआई मॉडल को प्रशिक्षण देना बहुत आसान बना दिया है।

वर्ष 2022 के अंत में जब ओपन एआई ने एआई

यूपी विधानसभा: हंगामे के नाम रहा पहला दिन, जयश्री राम के नारे के जवाब में लगे जय आंबेडकर के नारे, हुई नौकझोंक



.नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

लखनऊ। यूपी विधानसभा में बजट सत्र का पहला दिन हंगामे के नाम रहा। सत्ता और विपक्ष दोनों ही तरफ से जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण शुरू करते ही सपा के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच करीब 46 पेज के अभिभाषण वह आठ मिनट ही पढ़ पाई। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों को जनकल्याणकारी बताया। विधान मंडल के संयुक्त सदन की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। उन्होंने महाकुंभ को श्रेष्ठ भारत की अवधारणा

करार दिया। मौनी अमावस्या पर घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख जताया। वह सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों का जिक्र भी किया। राज्यपाल के अभिभाषण शुरू करते ही सपा के विधायक बेल में आ गए वे राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाने लगे। वे हाथ में नारे लिखे तख्तियां लेकर आए थे। हंगामा बढ़ता देख राज्यपाल ने पूरा 46 पेज का अभिभाषण पढ़ने के बजाय आठ मिनट में ही समाप्त कर दिया। इस बीच सत्ता पक्ष की तरफ से जय श्रीराम और विपक्ष की ओर से जय आंबेडकर के नारे भी लगे। विरोध बढ़ता देख सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोबारा 12.30 बजे

सदन की कार्यवाही शुरू हुई और विधायी कार्य निपटाए गए। **मिल्कीपुर विधायक ने ली शपथ** विधानसभा की कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने मिल्कीपुर के विधायक चंद्रभानु पासवान को शपथ दिलाने का प्रस्ताव रखा। विधानसभा अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित विधायक को शपथ दिलाई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने जयश्रीराम का नारा लगाया तो मुख्यमंत्री मुस्कराते रहे। विधायक ने भी शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री के सामने पहुंच कर आभार जताया। इसी

सत्ता की चामी से ही समाज की समस्याओं का मिलेगा समाधान :विगेस ठाकुर

चांदा के छतौना में जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

चांदा सुल्तानपुर। संगठित होकर के ही राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दौर में एक प्रतिशत से कम जाति समूह के लोग सत्ता में भागीदार बनकर अपने लोगों का हित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नई समाज दो प्रतिशत से अधिक तादाद में है। इसके बावजूद कई चुनाव से किसी भी राजनीतिक दल में एक विधायक तक नहीं पा सकता है।

उक्त उद्गार जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विगेस ठाकुर ने चांदा के छतौना गांव में आयोजित सभा में व्यक्त किया। श्री ठाकुर ने सजातीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जमाने से हम एक ईमानदार,भरोसे के लोग रहे हैं। बावजूद इसके राजनीतिक इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आवश्यकता है कि हम



एकजुट होकर के आगामी 2027 के चुनाव में अपनी ताकत का एहसास राजनीतिक दलों को करने का कार्य करें। सभा को संबोधित करते हुए राजेश शर्मा ने कहा हमारा विरोध किसी जाति धर्म से नहीं है। हम अपना हक मांगने के लिए आवाज उठा रहे हैं। महानंद सभा के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आवश्यकता है कि हम सब भी एकजुट होकर, एक मत होकर विगेस ठाकुर के हाथों को मजबूत

करें। ताकि हमारी आवाज भी सत्ता के गलियारों में बुलंद हो सके। इसके पूर्व अतिथियों ने भारत रत्न कपूर्ती ठाकुर, चक्रवर्ती महानंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया। अतिथियों का रविशंकर शर्मा, श्याम शंकर शर्मा ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर दीपक शर्मा, राम शंकर, उमाशंकर मथुरा प्रसाद शर्मा के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आयोजक रविशंकर शर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

गोवर्धन में गृहस्थ संत गोलोकवासी सुरेश चंद्र अग्रवाल स्मृति द्वार का लोकार्पण



नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

मथुरा। गोवर्धन में प्रमुख उद्योगपति एवं गृहस्थ संत गोलोकवासी सुरेश चंद्र अग्रवाल की स्मृति में श्री गिरिराज मुकुट मुखारविंद मंदिर पर श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल स्मृति द्वार का लोकार्पण मनीष बाबा (श्री जी पीठाश्वर) के आचार्यत्व में परम पूज्य संत सियाराम बाबा (हनुमान बाग) द्वारा किया गया। इस अवसर पर संत सियाराम बाबा ने कहा कि सुरेश चंद्र अग्रवाल पुण्य आत्मा थे। उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सरल तरीके

धार्मिकता के साथ व्यतीत किया उनके द्वारा किए गए कार्य लोगों द्वारा आज भी याद किए जाते हैं। अब उनकी इसी परंपरा को उनके पुत्र एवं ट्रस्ट के ट्रस्टी सुनील अग्रवाल द्वारा अनवरत चलाया जा रहा है वास्तव में धन का सदुपयोग किस तरीके से किया जाता है यह इस परिवार से सीखने योग्य है । इस परिवार द्वारा कोरोना के वक्त भी लगातार दिल खोलकर जनता की सेवा की वैक्सीन के कैप लगवाएं गए दवाइयां वितरित की गई भोजन बटवाया गया इसके अलावा आज भी गावों को

चारा गरीबों को भोजन व कोई भी सामाजिक कार्य हो उसमें यह परिवार पर चढ़कर हिस्सा लेते है । कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने की संचालन मंदिर के रिसीवर कपिल चतुर्वेदी द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीमती रजनी अग्रवाल लव बंसल व नंदिनी बंसल द्वारा किया गया। इस मौके पर डॉ शशांक माहेश्वरी आर्किटेक्ट संदीप बजाज डॉ ऐ के सैनी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे ।

ये अध्यादेश पटल पर रखे गए

- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन 2025)
- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यायदेश संख्या 2, 2025)।
- राज्य खाद्य आयोग के वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 तक के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट।
- खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का 2017-18 और 2018-19 की संकलित आर्थिक विवरण।
-राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 2018 से 2021 का वार्षिक लेखा विवरण।

इन अधिनियमों को मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश विनियोग (2024-25 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक 2024
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2024
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पांचवां, छठवां, सातवां व आठवां संशोधन) विधेयक 2024
उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2024
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2024
उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक 2024
उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2024
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक 2024

बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और विधायक कैलाश नाथ शुक्ल के जन्मदिन की बधाई दी। भाषा को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नौकझोंक हुई। विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। दरअसल, दोपहर 12.30 बजे के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भाषागत बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब सदन की कार्यवाही पांच भाषाओं में सुनी जा सकती है। शून्य नंबर पर सदन की भाषा है, जबकि एक नंबर पर अवधी, दूसरे पर भोजपुरी, तीसरे पर ब्रज,

चौथे पर बुंदेली और पांचवे पर अंग्रेजी है। इस पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजी को सदन से बाहर किया गया। यह हिंदी को कमजोर करने का प्रयास है। ज्यादा जरूरी है तो अंग्रेजी के बजाय उर्दू भाषा भी रखी जाए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना चाहते हैं। भाषा को समझ करने के प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार इन भाषाओं की एकेडमी बना रही है। विरोध की निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्दू की वकालत करना सपा का दोहरा चरित्र उजागर करता है।

मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डालने पर महिला को घर में घुसकर पीटा

मथुरा। महिला ने युवक के मोबाइल नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इससे युवक इतना क्रोधित हो गया कि वह अपने साथियों के साथ महिला के घर में घुस गया और उन पर हमला कर दिया। महिला ने हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। हाईवे थाना क्षेत्र स्थित एक कॉलोनी निवासी महिला ने बताया कि उनके पति बाहर काम करते हैं। वह बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती हैं। 13 फरवरी को फरह के गांव कहेरपुरा निवासी मनमोहन पचौरी अपने दो साथियों के साथ घर आया। उसने घर आते ही कहा कि मेरा मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डालने की हिम्मत कैसे की। महिला ने उसे घर से बाहर निकलने को कहा तो पर क्रोधित हो गया। आरोप है कि युवक ने अपने साथियों के साथ महिला पर हमला कर दिया। महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग बचाने के लिए आए। लोगों को आता देख आरोपी दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। हाईवे थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार शाही ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता की मूल भावनाओं के प्रति छात्रों व समाज को जागरूक बनाने के

शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता की मूल भावनाओं के प्रति छात्रों व समाज को जागरूक बनाने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर प्रारम्भ मथुरा। सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता की मूल भावनाओं के प्रति छात्रों व समाज के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने के भाव के साथ बीएसएफ कॉलेज मथुरा राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रथम व द्वितीय इकाईयों का एक सम्मिलित शिविर महावन के श्री गुरु काणि इण्टर कॉलेज में प्रारम्भ हुआ। इससे पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाईयों के 50-50 छात्र/छात्राओं और कार्यक्रम अधिकारियों के इस दल की बस को प्राचार्य डॉ. ललित मोहन शर्मा ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार से हरी झण्डी दिखाकर रवाना



किया। सात दिवसीय शिविर का शुभारम्भ मुख्य अतिथि व आध्यात्मिक गुरु संत हरदेवानन्द महाराज कार्यक्रम अध्यक्ष दिनेश मिश्र विशिष्ट अतिथि जितेन्द्र कुमार मिश्र प्रधानाचार्य ब्रजकिशोर सिंह प्राचार्य डॉ. ललित मोहन शर्मा ने माँ सरस्वती एवं बाबू शिवनाथ जी के चित्रपट पर द्वीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि सेवा ही

धर्म है और राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम से जुड़कर छात्र देश, समाज और स्वयं का बेहतर विकास कर सकते हैं। प्राचार्य डॉ. ललित मोहन शर्मा ने राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे कार्यक्रमों को छात्र जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया। साथ ही इस तरह के शिविरों से समाज और विद्यार्थियों में एक बेहतर समन्वय स्थापित होता है जो कि अन्ततः ज्ञान भाव और विद्या भाव की स्थापना में सहयोगी बनता

है। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शान्तनु एवं डॉ. चंचल शर्मा ने बताया कि प्रथम दिन शिविर में छात्रों ने श्री गुरु काणि इण्टर कॉलेज परिसर में एक वृहद् स्वच्छता अभियान चलाया तथा द्वितीय सत्र जागरूकता कार्यक्रमों के नाम रहा जिसमें शिविर के आस-पास के बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल-कल्याण, महिला कल्याण से जुड़े हुए मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में प्रो. एसके कटारिया प्रो यूके त्रिपाठी प्रो बीके गोस्वामी प्रो रवि शर्मा डॉ. चंचल शर्मा डॉ. रेखा राय डॉ. शांतनु कुमार डॉ. सत्येंद्र त्रिपाठी डीआर अपर्णा शर्मा रविंद्र सिंह रघुवीर सिंह चंद्र मोहन गोविंद सैनी डॉ. वी पी राय प्रोफेसर मुकेश चंद्र प्रो मुकेश चंद्र प्रो. एसके सिंह प्रो. बी बी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

एसपी यातायात को डंडा लेकर उतरना पड़ा सड़क पर

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

मथुरा। शहर में बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एसपी ट्रैफिक को डंडा लेकर सड़क पर उतरना पड़ा। दो घंटे तक पैदल चलते हुए 24 चालान कटवाए। सफेद पट्टी के अंदर खड़ी कार को क्रैन से उठवाया। एसपी ट्रैफिक की कारवाई से टेंपो, ई-रिक्षा के साथ कार व बाइक सवारों में अफरा-तफरी मची रही।नए बस स्टैंड से भूतेश्वर चौराहे तक सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहन, टेंपो व ई-रिक्षा शहर में जाम की समस्या बनाए हैं। नए बस स्टैंड, बीएसएफ कट, भूतेश्वर तिराहा, अग्निशमन



ऑफिस कट, सौंख रोड, कुष्णा नगर चौराहा और गोवर्धन चौराहे पर कई टीएसआई समेत कांस्टेबल तैनात हैं। फिर भी सड़क पर सफेद पट्टी के अंदर वाहनों का खड़ा होना कम नहीं हुआ। एसपी यातायात मनोज कुमार यादव नए बस स्टैंड पहुंचे। यहां पर सड़क को घेरे

खड़े आड़े-तिरछे टेंपो व ई-रिक्षों को देख डंडा लेकर हटवाना शुरू कर दिया। टेंपो व ई-रिक्षा चालकों को सड़क किनारे लाइन से चलने की नसीहत दी। इसके बाद पैदल चलते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों 24 वाहनों के चालान कटवाए।

यूपी बोर्ड परीक्षा: राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से होगी सभी 75 जिलों की निगरानी, परीक्षा केंद्रों पर होगी निगरानी

लखनऊ। यूपी बोर्ड परीक्षा में निगरानी के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया है। इस कंट्रोल रूम से पूरे प्रदेश के सभी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर निगाह रखी जाएगी। प्रदेश में 24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके तहत तीन स्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यह एक हफ्ते पहले सक्रिय हो गया है। यहां लगे 54 कंप्यूटर से सभी 75 जिलों के केंद्रों की निगरानी की जाएगी। बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी व नकल आदि पर रोकथाम लगाने के लिए विभिन्न स्तर पर व्यवस्था की जा रही है। इसी के तहत जिला, क्षेत्रीय कार्यालय व राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। राज्य स्तर पर बने कंट्रोल रूम से सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों

की अलग-अलग निगरानी की जाएगी। मंगलवार से इन कंप्यूटर को सक्रिय कर दिया गया है। इसके माध्यम से सीसीटीवी ठीक तरीके से चल रहे हैं या नहीं, स्टॉन रूम में बने कैमरे सक्रिय हैं या नहीं, व्यवस्थाओं आदि की जांच की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों ने बताया कि यहां ड्यूटी में लगे शिक्षकों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वह किस तरह से काम करेंगे, उन्हें परीक्षा के दौरान किन-किन चीजों की निगरानी करनी है। उन्होंने बताया कि केंद्र में किसी तरह की आपत्तिजनक स्थिति मिलने पर यहां से सीधे संबंधित केंद्र को फोन कर इसे ठीक कराया जाएगा। इसी क्रम में बोर्ड परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए टोलफ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट भी जल्द सक्रिय कर दिए जाएंगे।

जिला कारागार में बंदी फल और सब्जियों से बना रहे रंग-गुलाल

.नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

मथुरा। ब्रज में होली का उल्लास शुरू हो गया है। जिला कारागार में बंदी भी फल और सब्जी से गुलाल और रंग बनाने में जुट गए हैं। पूरी तरह से प्राकृतिक गुलाल और रंगों की बिक्री के लिए जेल प्रशासन स्टॉल लगाएगा ताकि लोगों को पूर्ण प्राकृतिक रंग आसानी से उपलब्ध हो सकें।

होली के त्योहार को देखते हुए दुकानदारों ने रंग और गुलाल का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। बाजार में रंग और गुलाल बिक्री के लिए उपलब्ध होने लगे हैं। केमिकल रंगों से लोगों को नुकसान होता है। इसलिए जिला जेल में 15 बंदी फल और सब्जी से पांच तरह के रंग और गुलाल बना रहे हैं। जेल अधीक्षक अशुंमन गर्ग ने बताया कि बंदी लाल, पीला, हरा, नीला और



गुलाबी रंग तथा गुलाल बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि लाल गुलाल और रंग में चुकंदर और गाजर, हरे रंग में पालक, नीले रंग में नील, गुलाबी रंग और गुलाल में चुकंदर और पीले रंग में हल्दी का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो बंदी रंग और गुलाल बना रहे हैं उन्हें पहले से यह कार्य आता था। प्राकृतिक रंगों से गुलाल बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद

उन्होंने 15 किलो रंग और गुलाल सैंपल के तौर पर बनाकर तैयार कर लिया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि बंदी जो रंग और गुलाल बनाएंगे उसकी बिक्री के लिए जिला कारागार के बाहर स्टॉल लगाया जाएगा। इसके अलावा शहर में भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर भी स्टॉल लगाया जाएगा। ताकि लोगों को पूरी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं से बना रंग और गुलाल आसानी से उपलब्ध हो जाए।

युद्धस्तर पर वादकारियों को तामील कराएं सम्मन और नोटिस

हमारा आंगन, हमारे बच्चें कार्यक्रम का किया गया आयोजन

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

चित्रकूट ब्यूरो: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में आगामी आठ मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में मंगलवार को जनपद में कार्यरत प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों के साथ द्वितीय चरण की बैठक आयोजित की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज नीलू मैनवाल ने बताया कि बैठक में जनपद न्यायाधीश ने आगामी आठ मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निस्तारण के लिए बल दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक



वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम वाद, श्रम वाद, बैंक वसूली वाद, विद्युत अधिनियम, जल वाद, सर्विस मैटर्स, पारिवारिक व वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, राजस्व व चकबन्दी वाद, किरायेदारी वाद, सुखाधिकार वाद, स्थायी निषेधाज्ञा व सिविल वाद, मनी वसूली वाद, विनिर्दिष्ट अनुतोष वाद, मोटर वाहन ई-चालान व लघु आपराधिक वाद, आमवाद, प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं

(विशेषकर पारिवारिक मामले), उपभोगता फोरम तथा आर्बिट्रेशन सम्बन्धित वादों का निस्तारण किया जाना है। जिला जज ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी अपने विभागों से सम्बन्धित समस्त ऐसे मामले, जिनको लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा सकता है, को अधिक से अधिक चिन्हित कर उनमें पक्षकारों को कम से कम दो बार नोटिस तामीला कराते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने का प्रयास

करें। इस मौके पर एससी/एसटी कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश व राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी राममणि पाठक, जिला विकास अधिकारी प्रियंका यादव, जिला प्रोवेशन अधिकारी पंकज कुमार मिश्रा, जिला आपूर्ति अधिकारी अनुज कुमार पटेल, परिवहन अधिकारी दीप्ती त्रिपाठी, एसटीए अंकुर कचेर, वरिष्ठ बाट-माप अधिकारी शरद कुमार पाण्डेय, उपवनाधिकारी राजीव रंजन सिंह, खनिज निरीक्षक मंटू कुमार सिंह, उपखण्ड अधिकारी विद्युत आशीष सिंह, अवर अभियन्ता यतेंद्र कुमार, चकबन्दी अधिकारी शरदचन्द्र यादव, उपश्रमायुक्त आरके गुप्ता, अवर अभियन्ता पीडब्ल्यूडी बलराम प्रजापति, अधीक्षक अभियन्ता पीडब्ल्यूडी वेद नारायण, जिला पंचायतराज अधिकारी इन्द्रनारायण सिंह आदि मौजूद रहे।

पुलिस अधीक्षक ने किया पहाड़ी थाने का आकस्मिक निरीक्षण

पहाड़ी, चित्रकूट: पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने मंगलवार को थाना पहाड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र में अतिक्रमण न होने देने तथा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टित भ्रमण करने के निर्देश दिए। थाना पहाड़ी के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर की साफ-सफाई व कार्यालय में रजिस्ट्ररों के उचित रख-रखाव, बंदीगृह, सीसीटीएनएस कार्यालय, प्रभारी निरीक्षक कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क एवं



नवनिर्मित भवन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को थाना परिसर, नवनिर्मित भवन एवं मंदिर की रंगाई-पुताई कराने तथा बन्द पड़े कूलर, पंखा, बिजली आदि की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी महाशिवरात्रि व अमवस्या मेले के दृष्टित क्षेत्र

इंडियन बैंक की तरौंहा शाखों में किया गया एटीएम मशीन का उद्घाटन

चित्रकूट ब्यूरो: इंडियन बैंक शाखा तरौंहा (कर्वी) में मंगलवार को एटीएम/कैश जमा मशीन का उद्घाटन किया गया। साथ ही वृहद ग्राहक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नरेन्द्र गुप्ता ने कहा कि



इंडियन बैंक द्वारा ग्राहकों की सुविधा के लिए एटीएम मशीन लगाई गई है। उन्होंने ग्राहकों को सरकार द्वारा जिला इंडियन बैंक के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी तथा पात्रों को लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। एलडीएम अनुराग शर्मा ने विस्तार से

संक्षिप्त समाचार

दो पक्षों में हुई मारपीट, क्रॉस केस दर्ज

ललितपुर थाना जखौरा के ग्राम मैनवारा में दो पक्षों के बीच एक-दूसरे के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। प्रथम पक्ष से ग्राम मैनवारा निवासी श्रीराम पुत्र सुकुन अहिरवार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 15 फरवरी को वह गांव में था, तभी गांव का अमोल पुत्र धर्मा आ गया और अकारण गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर चला गया। तो वही दूसरे पक्ष से ग्राम मैनवारा निवासी रेखा पत्नी अमोल ने पुलिस को तहरीर देकर विपक्षी श्रीराम पुत्र सुकुन अहिरवार सहित तीन नामजद आरोपितों पर गाली गलौज करते हुये मारपीट करने व मना करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाये है। पुलिस ने दोनो पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।

पिता-पुत्र के साथ मारपीट कर किया घायल

ललितपुर। महरौनी के ग्राम छपरट में पीडित व उसके पुत्र के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर घायल करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। थाना सौजना के ग्राम मैगुंवा निवासी चालीं राजा पुत्र रावराजा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते वह अपने पुत्र के साथ महरौनी के ग्राम छपरट में था, तभी ग्राम छपरट निवासी मुन्ना पुत्र चुन्नीलाल अपने एक नामजद व दो अज्ञात साथियों के साथ आकर पीडित व उसके पुत्र के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने लगा, आस-पास से लोगो को आता देख आरोपित जान से मारने की धमकी देकर चले गये। पुलिस ने मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

कस्बा जखौरा व बांसी में हुई मारपीट, मामले दर्ज

ललितपुर कस्बा जखौरा व कस्बा बांसी में दो व्यक्तियों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही की है। ग्राम बरौदास्वामी निवासी कैलाश पुत्र हरदास लोधी का आरोप है कि दो फरवरी को वह कस्बा जखौरा में था, तभी गांव का कृष्णपाल पुत्र गोविन्ददास अपने तीन अन्य साथियों के साथ आया और गाली गलौज कर मारपीट करते हुये जान से मारने की धमकी देने लगा। तो वही कस्बा बांसी देवकी पुत्र गोकल अहिरवार ने कस्बा बांसी में रहने वाले करन पुत्र रोशन सहित तीन आरोपितों पर गाली गलौज करते हुये मारपीट करने व मना करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाते हुये केस दर्ज करवाया है।

रालोद ने किसानों की उटाई समस्याएं सीएम के नाम तीन सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा

एनपीटी ब्यूरो ललितपुर

ललितपुर। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष परशुराम कुशवाहा के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं से संबंधित तीन सूत्री मांगों का ज्ञापन सीएम के नाम अपर जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्या का समाधान कराने की मांग की है। अपर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि जनपद में बहुत से



किसानों को उड़द की खराब हुई फसल का बीमा एवं राहत राशि नहीं मिल पाई है। इसी तरह किसान सम्मान निधि के लिए जो किसानों की आईडी बनाई जा रही हैं, उसमें भी बहुत से किसानों के

इस पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की इकाई ने किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सौरभ श्रीवास्तव, कबीर सिन्हा, वसीम शेख, नमन जैन, अमित कुशवाहा, वर्धन सिंह यादव, गौरव यादव, सुनील कुशवाहा, मोहित राजपूत, अखिल कुमार, श्रीकांत, पवन कुशवाहा, महेश चौबे, अभय यादव, सौरभ कुशवाहा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

करमई का सार्वजनिक शौचालय चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट

एनपीटी ब्यूरो ललितपुर

ललितपुर बार- ब्लाक मुख्यालय बार की कई ग्राम पंचायतो में प्रधान और सचिव ने मिलकर जमकर भ्रष्टाचार किया है और शासन द्वारा भेजी गयी धनराशि का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ग्राम पंचायत करमई में जनता की सुविधा के लिये और महिलाओ को खुले में शौच के लिये न जाना पड़े इसके लिये शासन से आयी धनराशि के द्वारा ग्राम प्रधान ने लगभग दो लाख उन्तालीस हजार की लागत से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया था जिसका उद्देश्य था की गांवो में गंदगी न फैले और न ही किसी को खुले में शौच जाना पड़े लेकिन बाबजूद इसके आज भी गांव के हालात बद से बदतर है जहां चारों ओर गंदगी फैली है गंदगी से नालियां बज बजा रही है सड़को पर गन्दा पानी फैल रहा है वही सामुदायिक शौचालय के भी चारो ओर गंदगी फैली है वही बड़े बड़े कचरे के ढेर लगे हुए है। लाखों रुपए की लागत से बना सार्वजनिक शौचालय अपनी दुर्दशा पर आज भी आंस् बहा रहा जो लोगों की सुविधाओ के लिये बना था उसे अब कचरा घर बना दिया गया है। मरम्मतीकरण के लिये निकली



धनराशि का हुवा बंदरबांट- करमई गांव में बने सार्वजनिक शौचालय को फिर उपयोग लाया जा सके इसके लिये प्रधान और सचिव ने शासन से मरम्मतीकरण को लेकर शिवानी कंट्रक्शन के नाम की फर्म को 33162 रुपये का भुगतान किया गया वही कंट्रक्शन इंजीनियर के नाम भी 688 रुपये का भुगतान किया गया बाबजूद इसके फिर भी हालात नहीं सुधरे क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ेइतनी मजबूत है कि काम के नाम पर सिर्फ अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अपनी जेबे गर्म कर जनता को मिलने वाली सुविधाओं में पलीता लगाने में लगे हुए है क्या प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को ठेगा दिखाने वालो पर कोई काराबाई अमल में लायी जायेगी है या यूँ शासन के पैसे को हवा में उड़ाया जाता रहेगा। शौचालय के टूटे गेट, टंकी गायब, चारों ओर फैली गंदगी-जिस शौचालय के

अवैध संयोजन से बिजली का हो रहा व्यवसायिक उपयोग, साड़ी लाइन का है पूरा मामला



एनपीटी ब्यूरो ललितपुर

ललितपुर। शहर के मध्य स्थित साड़ी लाइन में कुछ दुकानदारों द्वारा घरों से विद्युत संयोजन का अवैध कटिया डालकर व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त कपड़ों की दुकान में जब अवैध कटिया संयोजन से स्पाकिंग की खबर अन्य दुकानदारों को लगी, तो उन्होंने उक्त दुकानदार से अवैध संयोजन हटाकर विधिवत तरीके से विभागीय फीस जमा कर विद्युत संयोजन लेने की बात कही, जिस पर उक्त दुकानदार ने अन्य दुकानदारों पर आग बबूला होते हुये भगा दिया। गौरतलब है कि कपड़ों की दुकानों के बीच अवैध संयोजन के चलते किसी घटना-दुर्घटना होने की संभावनाएं भी काफी बलवती होती है। इस सम्बन्ध में जानकारी करने पर लोगों ने दबी जुबान में बताया कि किसी अन्य के घर से तार डालकर अवैध तरीके से विद्युत का प्रयोग व्यवसायिक रूप में किया जा रहा है, जिससे कि कभी भी कोई दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से मामले का सज्ञान लेकर विद्युत विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित करते हुये उक्त दुकान पर छापेमारी कराकर अवैध संयोजन को हटवाये जाने की मांग उठायी है।

ऑपरेशन करने के नाम पर दस हजार रुपये मांगने का आरोप

एनपीटी ब्यूरो ललितपुर

ललितपुर शहर क्षेत्र के ग्राम रजवारा में रहने वाली संगीता पत्नी राजेन्द्र ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र भेजा है। पत्र में महिला ने बताया कि करीब 10 दिन पहले उसके पति राजेन्द्र का एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट के बाद उसके पति का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा था। आरोप है कि जिला अस्पताल में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ ने उसके पति का एक्स-रे निकलवाया, जिसमें फ्रैक्चर होना बताते हुये ऑपरेशन किये जाने की बात कही। पीडिता ने बताया कि एक्स-रे निकालने के बाद चिकित्सक के साथ रहने वाले युवक आये और उससे ऑपरेशन के नाम पर दस हजार रुपये की मांग की गयी। आरोप है कि दस हजार रुपये न देने पर विगत दस दिनों से ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। यह भी बताया कि जब उसने आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करना चाहा तो उसके बावजूद भी रुपयों की मांग की जाने लगी। पीडिता ने जिला प्रशासन से मामले की जांच करायी जाकर कार्यवाही किये जाने की गुहार लगायी है।



खैरथल के ओवरब्रिज निर्माण में नेताओं की दखल अंदाजी से आमजन में निराशा

वर्षों से जाम में फंसने का झेल रहे है दर्द

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

खैरथल-तिजारा: खैरथल के फाटक सं. 93 पर ओवरब्रिज पर पुलिया निर्माण का सालों से सपना देख रही जनता का सपना पूरा होगा। या एक बार फिर स्थानीय जुम्मेवारों की भूमिका से सपना तोड़ दिया जाएगा यह विचार खैरथल के लोगों की जुबान पर आज ये ही चर्चा है एमडीआर 25 पर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित ओवरब्रिज का मैप सामने आने और एन ओसी लेने का पत्र जैसे ही सामने आया कुछ नेता वर्षों से

पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा करे बैठे लोगों के समर्थन में उतर अपने सुझाव और भाजपा सरकार होने के गुरूर में विकास कार्यों को रोकने के लिए लामबंद होने लगे है **पहले भी खेल चुके है खैल-** रेलवे द्वारा सन् 2018 में राजस्थान में बनने वाले ओवरब्रिज की लिस्ट में भी फाटक सं93 पर ओवरब्रिज बनाया था,पिछली गेहलोत सरकार ने इसके लिए राशि भी आवंटित की मगर नेताओ,जमीन कारोबारी और अधिकारियों और कुछ खैरथल विकास की बात करने वाले लोगों ने

मिलकर ऐसा खेल खेला सब कुछ अटका रहा और 93न. पर बनने वाले इस ओवरब्रिज के बदले बाईपास पर ओवरब्रिज पास करवा लिया जिसका निर्माण निकट भविष्य में होना है इसके बनने से भी खैरथल में लगने वाले भारी जाम से जनता को राहत मिलने वाली नही है अतिक्रमण कब्जो को बचा लिया गया अब रेलवे देश में हाई स्पीड चलाने के लिए लोह बाड और फाटक बंद करने जा रहा है इसके लिए अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनाये जा रहे है रेवाड़ी से जयपुर के बीच बिजी

फाटक सं93 पर केंदमी सरकार ने ओवरब्रिज बनाने के लिए मैप जारी किया एन ओसी की कारवाही शुरू की है इस फाटक पर हर महिने एक घटना फाटक टूटने की होती है वही पुराना खेल अब शुरू है गया है ओवरब्रिज निर्माण रोकने जगह को इधर उधर करने के लिए पहले पैरवी करने वाले तो राजनिति का बनवास भोग रहे है अब कौन नया पैरवीकार बनेगा और अपनी राजनिति को दाव पर लगायेगा देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि यह जनता है जाम से दुखी मौके पर जबाब देती है

पनोरमा स्पोर्ट्स अकेडमी गुढ़ा गौड़जी में दो दिवसीय कबड्डी लीग प्रतियोगिता का समापन कोच बजरंग पहलवान के नेतृत्व में जीता खिताब

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

शुंझुनू गुढ़ागौड़जी। सोमवार को पैनोरमा स्पोर्ट्स अकेडमी में दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में माइक का संचालन मुकेश गुर्जर ने किया। प्रतियोगिता में कुल 30 टीमों ने भाग लिया जिसमें प्रथम प्रचलंगी की टीम रही द्वितीय पोंख ग्रामीण तथा तृतीय पोंख नगर पालिका की टीम रही जिनको डॉक्टर विकास गिल,वीरेंद्र साहू, सुमित्रा सिंह ने प्रथम विजेताओं को 21 हजार,द्वितीय विजेताओं को



11 हजार तथा 5100 सो रूपयों का नकद पुरस्कार देकर विजेताओं को सम्मानित किया । पोंख ग्रामीण टीम के कप्तान सुनील खल्वा, संदीप

सैनी ने बताया कि हमारे कोच बजरंग पहलवान हमें अच्छी मेहनत करवाते हैं उनके आशीर्वाद से ही यह किताब हमने हासिल किया है ।

अवैध बजरी खनन में पुलिस की सांठगांठ उजागर

5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर 17 सीसीए का नोटिस थमाया

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

नागौर । जिले के रियाबड़ी उपखंड में अवैध बजरी खनन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए डिकॉय ऑपरेशन में थांवल्ला थाना क्षेत्र के 4 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद इन सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही थानाधिकारी समेत सभी पांच पुलिसकर्मियों को 17 सीसीए का नोटिस भी थमाया गया है।

रियाबड़ी उपखंड में लुणी नदी के आसपास लंबे समय से अवैध बजरी खनन की शिकायतें मिल रही थीं। ग्रामीणों ने कई बार जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि पुलिस के कुछ कार्मिक बजरी माफियाओं से सांठगांठ कर करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान करवा रहे थे। जब इस मामले की भनक पुलिस मुख्यालय को लगी तो उच्च अधिकारियों ने विजिलेंस टीम का गठन कर डिकॉय ऑपरेशन चलाया।



इस कार्रवाई में थांवल्ला थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल चंद्रगुप्त और कांस्टेबल शंकरलाल मीणा, विजयसिंह व गोविंदराम की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी सूरजमल सहित सभी पांच आरोपियों को लाइन हाजिर कर दिया गया।

रेंज डीआईजी ओमप्रकाश ने बताया कि नागौर जिले में अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके चलते पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर विजिलेंस टीम ने जांच की। डिकॉय ऑपरेशन के तहत मिली रिपोर्ट में थांवल्ला थाने के कई पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। डीआईजी ने साफ किया कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिवादी ने कई बार लिखित शिकायतें दी थीं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा, तो विजिलेंस टीम ने ऑपरेशन चलाकर सच्चाई उजागर की। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और अब अन्य एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं।

इस कार्रवाई से साफ हो गया है कि अवैध बजरी खनन में केवल माफिया ही नहीं, बल्कि पुलिसकर्मी भी शामिल थे। अब देखना होगा कि दोषियों पर आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दौरा, बोले- यहां बहुत पहले आना चाहिए था



चित्तौड़गढ़ । उदयपुर में एक बैठक में शामिल होने आए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दुर्ग के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों जैसे व्यू प्वाइंट, राणा कुम्भा महल, विजय स्तंभ, समीदेश्वर मंदिर, कालिका माता मंदिर और सूरज पोल दरवाजे का अवलोकन किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आज शाम चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग का भ्रमण किया और इसके गौरवशाली इतिहास से रूबरू हुए। उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व की सराहना करते हुए कहा कि यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उन्हें बहुत पहले यहां आना चाहिए था। उदयपुर में एक बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री माणिक साहा चित्तौड़गढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुर्ग के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों जैसे व्यू प्वाइंट, राणा कुम्भा महल,

विजय स्तंभ, समीदेश्वर मंदिर, कालिका माता मंदिर और सूरज पोल दरवाजे का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने चित्तौड़गढ़ को वीरता, त्याग और संस्कृति का प्रतीक बताया। दुर्ग भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से इसकी सुरक्षा और संरक्षण को लेकर जानकारी ली। उन्होंने दुर्ग की ऐतिहासिक धरोहर को संजोने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस दौरान गाइड सुधीर कुमार ने मुख्यमंत्री को दुर्ग के गौरवशाली इतिहास की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री के इस भ्रमण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह और पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री साहा उदयपुर के लिए रवाना हो गए।

अवैध खनन पर पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त छापेमारी



नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

खैरथल-तिजारा, 18 फरवरी। जिले में अवैध खनन एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। हसनपुरमाफी और मुण्डावर क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए टीम ने 1 जेसीबी, 1 डम्पर और 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए।

खनिज अभियंता ने बताया कि जब्त किए गए वाहनों में खनिज साधारण मिट्टी का अवैध रूप से खनन और परिवहन किया जा रहा था। सभी जब्त वाहनों को संबंधित पुलिस थाने में सुपुर्द कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

खनिज अभियंता ने बताया कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा तथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशिक्षु कांस्टेबल की ट्रेनिंग के दौरान हुई मौत, डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की संभावना जताई

चित्तौड़गढ़ । झालरा पाटन पीटीएस में ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षु कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ने के कारण मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की संभावना जताई है। बहरहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ पुलिस में भर्ती प्रशिक्षु कांस्टेबल को झालरा पाटन स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। प्रशिक्षु कांस्टेबल चित्तौड़गढ़ जिले में बडोली माधोसिंह का रहने वाला है। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजन झालरा पाटन पहुंचे। स्थानीय पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।

जयपुर शहर के नए जिलाध्यक्ष बने अमित गोयल, सर्वसम्मति से हुआ निर्वाचन

4 जिलों में अब भी चुनाव बाकी

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

जयपुर । जयपुर शहर से भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। हम सब मिलकर आगामी नगर निगम चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाएंगे।



भारतीय जनता पार्टी संगठन में 44 जिलाध्यक्षों के निर्वाचन में से 40 का चुनाव हो चुका है। इसी कड़ी में जयपुर शहर के लिए अमित गोयल को भाजपा का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जयपुर शहर में वैश्य समाज को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने यह निर्णय लिया, क्योंकि पार्टी को ब्राह्मण और वैश्य समाज पर मजबूत पकड़ है।

जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष पद के लिए कुल 14 दावेदारों ने नामांकन किया था, जिनकी सुनवाई सिविल लाइन्स स्थित सामुदायिक केन्द्र में निर्वाचन अधिकारी ने की। इसके बाद सर्वसम्मति से अमित गोयल का नाम प्रस्तावित किया गया।

जिलाध्यक्ष बनने के बाद अमर उजाला से बातचीत करते हुए गोयल ने कहा- रमैं सबसे पहले संगठन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का

धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मेरी प्राथमिकता होगी कि हम सब मिलकर तेजी से पार्टी के काम को आगे बढ़ाएं और आगामी नगर निगम चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाएं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देना होगी, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं।

बीजेपी ने जयपुर शहर में वैश्य समाज को जिलाध्यक्ष बनाकर अपने कोर वोटर को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। जयपुर में वैश्य और ब्राह्मण समाज बीजेपी के परंपरागत समर्थक हैं। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक पहले से यह तय था कि जयपुर शहर का अध्यक्ष वैश्य समाज से ही होगा।

जिला अध्यक्ष पद के लिए पुनीत कर्णावट सबसे प्रमुख दावेदार थे, लेकिन उनके नाम पर कुछ विधायकों को आपत्ति थी, जिनमें विधायक कालीचरण सराफ का नाम शामिल है। हवामहल से पार्षद विमल अग्रवाल और राजेश तांबी के नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद अमित गोयल का चयन किया गया।

अजमेर । बिजयनगर में स्कूली छात्राओं से सोशल मीडिया पर दोस्ती करके उन्हें ब्लैकमेल किए जाने का मामला उजागर होने के बाद आज नाबालिग पीड़िता ने कोर्ट में अपने और अपनी सहेलियों के शोषण की दास्तान सुनाई। उधर कोर्ट में पेशी के दौरान मामले में वकीलों का गुस्सा फूटा और उन्होंने आरोपियों को पीट दिया।

ब्यावर के बिजयनगर ब्लैकमेलिंग मामले में आज सुबह कोर्ट में नाबालिग पीड़िताओं के कलमबद्ध बयान दर्ज किए गए। इस दौरान उनके परिजन और हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी नसीराबाद कोर्ट परिसर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट परिसर के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था।

मामले में पुलिस ने नाबालिग बच्चियों के शोषण के आरोप में समुदाय विशेष के सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से पांच बालिग और दो नाबालिग हैं। बालिग आरोपियों को अजमेर न्यायालय में पेश कर पुलिस ने रिमांड की मांग की गई है, ताकि उनसे पूछताछ कर मामले से जुड़े और सबूत जुटाए जा सकें। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों को मौके पर ले जाकर तस्दीक भी करवाएगी। वहीं दो नाबालिग आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड भेजा

शोषण

बिजयनगर ब्लैकमेल मामले में पीड़िता ने सुनाई शोषण की दास्तान

आरोपियों पर वकीलों का गुस्सा फूटा



जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी ब्यावर भीपेंद्र शर्मा ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी।

पीड़िता ने सुनाई शोषण की दास्तान

बिजयनगर कांड में पीड़ित लड़की ने कोर्ट में अपनी दुखद कहानी साझा करते हुए बताया कि कैसे उसे जबरन दोस्ती करने के लिए मजबूर किया गया और फिर उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया गया। लड़की ने बताया कि जब वह और उसकी सहेलियां स्कूल जाती थीं, तो कुछ लड़के उनका पीछा करते थे। इसके बाद वह लड़के उन्हें शाम को भी परेशान करते थे और फिर चिट्ठियां फेंकने लगे। जब पीड़िता ने उनसे बात करना शुरू किया, तो पता चला कि वह लड़के अलग धर्म से थे।

लड़के ने बाद में उसे छोटे मोबाइल फोन देने शुरू किए और

बाहर घुमाने भी ले जाने लगे। धीरे-धीरे उसने पीड़िता पर विश्वास जमाया और फिर उसकी फोटो खींची। इसके बाद ब्लैकमेल करके पांच लड़कों से दोस्ती कराई और उसे खास प्रकार के कपड़े पहनने के लिए कहा गया। इसके साथ ही उसे समाज के कुछ तरीकों के बारे में भी बताया गया।

पीड़िता ने यह भी खुलासा किया कि लड़कों ने उसे अन्य लड़कियों से दोस्ती करने के लिए दबाव डाला। उनका इरादा इन लड़कियों को बेचने का भी था। रिश्तेदारों ने बताया कि एक लड़की को पांच से दस लड़के परेशान करते थे और लड़कियों को धमकाकर उनके हाथों में चाकू से कट लगा देते थे। लड़की इतनी घबराई हुई थी कि उसने कभी अपने परिवार को कुछ नहीं बताया।

जब पीड़िता के पास से छोटा मोबाइल फोन मिला तब जाकर मामले का खुलासा हुआ और

लड़कियों के परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया।

गौरतलब है कि बिजयनगर में स्कूली छात्राओं को दोस्ती के बहाने ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया था। मामले में एक छात्रा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ युवक नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर फंसाते और फिर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। इस मामले में 17 फरवरी को पीड़ित लड़कियों के परिजनों और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को हिरासत में लिया।

वकीलों ने आरोपियों को पीटा पेशी के दौरान कोर्ट लाए गए 6 आरोपियों पर वकीलों ने अपना गुस्सा निकाला। बड़ी मुश्किल से पुलिस आरोपियों को बचाकर ले गई। इससे पहले कोर्ट ने आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया। मामले में 6 आरोपियों रिहान मोहम्मद (20), सोहेल मंसूरी (19), लुकमान उर्फ सोहेब (20), अरमान पटान (19), साहिल कुरैशी (19) और अफराज (18) को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 1 नाबालिग को डिटेन किया है।

राज्य के सिविल सर्जन को सुविधाएं उनके पद के अनुरूप मिलेगा- डॉ इरफान अंसारी

एनपीटी ब्यूरो
झारखण्ड के हेमन्त कबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है। वे लगातार इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही राज्य के डॉक्टरों के लिए भी मंत्री इरफान अंसारी कई अहम फैसले ले रहे हैं। इसी बीच मंत्री इरफान अंसारी रविवार को झारखण्ड में सरकारी डॉक्टरों के संगठन झारखण्ड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन यानी झासा की नई निर्वाचित कमिटी के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे। जहां उन्होंने राज्य के डॉक्टर औ? सिविल सर्जन के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। कार्यक्रम की तस्वीरें मंत्री ने एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के पदस्थापना समारोह में शामिल होकर शुभकामनाएं दीं। नयी टीम के साथ मिलकर झारखण्ड की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देंगे। बता दें मंत्री इरफान अंसारी ने कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार राज्य में चिकित्सा के क्षेत्र और खासकर डॉक्टरों के लिए ऐसी पॉलिसी बनाने



जा रही है, जिससे दूसरे राज्यों के डॉक्टरों भी राज्य में सेवा देने के लिए आकर्षित होंगे। मंत्री ने इस दौरान बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि झारखण्ड के चिकित्सा सेवा संवर्ग के डॉक्टरों को भी बिहार के तर्ज पर डायनेमिक एसीपी का लाभ दिया जायेगा यानी झारखण्ड के डॉक्टरों को अब केन्द्र के तय मानकों की तर्ज पर प्रोन्नति का लाभ दिया जायेगा, बिहार में 2017 से डॉक्टरों को डायनेमिक एसीपी का लाभ दिया जा रहा है और अब बिहार की तर्ज पर झारखण्ड के डॉक्टरों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही झारखंड सरकार ने

राज्य के डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा की है। अब डॉक्टरों को अपनी पसंद की पोस्टिंग मिलेगी और बायोमैट्रिक्स हाजिरी की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब किसी भी डॉक्टर को अपनी मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिल सकेगी। सरकार ने यह निर्णय डॉक्टरों की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे डॉक्टरों को कार्यस्थल पर अधिक संतुष्टि मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी हस्तक्षेप को कम करते हुए डॉक्टरों की प्राथमिकताओं को महत्व दिया जाएगा। खासकर

ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, इसलिए डिजिटल उपस्थिति प्रणाली से उन्हें बाध्य करना उचित नहीं है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के सिविल सर्जन को सुविधाएं उनके पद के अनुरूप मिलेगा, जिले में उनके समकक्ष अधिकारी (उपायुक्त) होते हैं, इसलिए सुविधाएं भी उनके बराबर के उपलब्ध कराए जायेंगे। झारखण्ड सरकार अब अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए रिटायर्ड डॉक्टरों की सेवाओं को दोबारा लेने पर विचारकर रही है। साथ ही नये डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया को भी तेज किया जायेगा। मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। डॉक्टरों से अपील है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करें।

विधायक निशात आलम ने की अस्पताल का औचक निरीक्षण, दिया निर्देश



नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

झारखण्ड विधानसभा आम निर्वाचन- 2024 में सावधिक मतों से विजयी रहे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक निशात आलम ने 18 फरवरी 2025 मंगलवार को अचानक पाकुड़ सदर अस्पताल सोनाजोड़ी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था को ले ओपीडी, प्रसूति कक्ष, दवाई कक्ष, लैबरेटरी, यूएसजी कक्ष, डेंटल जांच व्यवस्था समेत जेनरल चेक अप सहित जेंट्स / महिला वार्ड अन्य की सुव्यवस्थाओं का जायेजा लिया। इस दौरान

उन्होंने मरीजों से कुशलक्षेम पूछा और हाल-चाल जाना। साथ ही मरीजों को आवश्यक उपचार की सभी अवयव समय पर उपलब्ध हो रही या नहीं मरीजों से जाना। विधायक निशात आलम ने निरीक्षण के पश्चात कई आवश्यक दिशा-निर्देश उपाधीक्षक डॉ मनीष कुमार को दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों की उपचार से सम्बन्धित सभी अवयवों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस विशेष ध्यान रखने की हिदायत स्वास्थ्य कमियों को दिया। विधायक निशात आलम ने डीएस डॉ मनीष कुमार से अस्पताल में सभी उपचार सम्बन्धी अवयवों की

उपलब्धता व कमियां की भी जानकारी ली। उन्होंने मरीजों की बेहतरीन सेवा व्यवस्था स्थापित करने हर एक पहलुओं पर बारीकी से निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा- निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान डीपीआरओ प्रीतिलता मुर्मू, डीएसओ अभिषेक कुमार सिंह, परियोजना पदाधिकारी मो. मतिउर रहमान, डीएस डॉ मनीष कुमार, डॉ अमित कुमार समेत कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्रीकुमार सरकार, प्रवक्ता मुख्तार हुसैन, प्रखण्ड अध्यक्ष मानसारुल हक, अल्पसंख्यक अध्यक्ष शाहीन परवेज, पियारुल

क्षेत्र वासियों की सुविधार्थ में विधायक ने समर्पित की दो एंबुलेंस, बने समिति की निगरानी में एंबुलेंस का होगा संचालन



एनपीटी ब्यूरो

पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक निशात आलम ने 18 फरवरी 2025 मंगलवार को क्षेत्र वासियों की हितार्थ में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था स्थापित करने व आपातकाल/ अकास्मिक (ईमेरजेंसी) सुविधा के ध्यानार्थ सुविधाएं बहाल करने की जरूरत की आपूर्ति हेतु अपने विधायक निधी फंड से दो एंबुलेंस मुहिया कराया। जिसका विधिवत उद्घाटन कांग्रेस कार्यालय परिसर से कांग्रेसी कार्यकर्ता समेत आमजनों की उपस्थिति में विधायक ने फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा

कि क्षेत्र वासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था स्थापित करने की उद्देश्य से ही यह एंबुलेंस उपलब्ध कराया गया। जरूरत पड़ने पर और भी उपलब्ध कराया जायेगा। वही विधायक ने पाकुड़ स्थित डीडीएच में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का विधिवत उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने यूएसजी सुविधा की आवश्यक तकनीकी उपलब्धता की जानकारी भी ली। तत्पश्चात विधायक निशात आलम ने पाकुड़ प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत पंचायत हिरानन्दनपुर के पियादापुर गांव समेत

भवानीपुर व फरसा पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने जनसमस्याओं से रुबरु हुए। तत्पश्चात आश्वस्त किया कि यथाशीघ्र आपके सभी समस्याओं का निष्पादन सम्बन्धित विभाग से कराया जायेगा। वही विधायक ने जनसम्पर्क के दौरान ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आपका सहयोग के बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंच सका। जिसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूं। कहा आपकी जब भी जरूरत हो, हमें साझा करें, ताकि आपके सेवा में अपना योगदान साझा कर सकें।

मुख्य सचिव वीसी के माध्यम से 20 फरवरी को करेंगे बैठक



एनपीटी ब्यूरो

पाकुड़ (झा०खंड), 20 फरवरी को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से होने वाली बैठक की तैयारीयों को लेकर उपायुक्त मनीष कुमार ने गोपनीय कार्यालय कक्ष में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक किया। उपायुक्त मनीष कुमार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज टू के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला को निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति का अनुश्रवण, ग्राम स्तर पर स्वच्छता, ठोस

एवं तरल कचरा प्रबंधन के क्रियान्वयन एवं निर्मित अवयवों के क्रियाशील रखने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने खराब पड़े सभी चापानल को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। बैठक में जल जीवन मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर ससमय योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

साथ ही उपायुक्त ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार, झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग एवं

नगर परिषद विभाग की समीक्षा कर लॉबित योजनाओं को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रशासक, नगर परिषद, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, माइनिंग इंस्पेक्टर समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

विधायक ने विजेता व उप विजेता टीम को किया सम्मानित



नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

बीते मंगलवार को हिरणपुर प्रखण्ड अन्तर्गत गोपालपुर मैदान में आदिवासी एभेन गाउता के द्वारा आयोजित फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में गाजीपुर (यूपी) टीम ने बोकरो को हराकर शील्ड पर कब्जा जमाया। जहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने विजेता व उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया। विधायक के आगमन पर आयोजक कमिटी द्वारा परंपरागत आदिवासी रितिरिवाज से उनकी जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। बीते 16 फरवरी से आयोजित इस टूर्नामेंट में झारखण्ड इस टूर्नामेंट में झारखण्ड सहित बिहार , बंगाल , यूपी के नामचीन टीम ने भाग लिया था। फाइनल खेल देखने को

लेकर हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित थे। वही खेल प्रारम्भ होने के पूर्व कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई थी। फाइनल खेल के दौरान दोनों टीम के बीच जमकर मुकाबला हुआ। जिसमें गाजीपुर टीम ने एक गोल से बाजी मारी। विधायक हेमलाल मुर्मू के द्वारा विजेता टीम को पांच लाख व उप विजेता टीम को चार लाख की राशि देकर पुरस्कृत किया गया। वही सेमि फाइनल में पहुंचे दो टीम को एक -एक लाख की राशि देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर झामुमो के सुलेमान बास्की , रंजन साहा, दानियल किस्कु, जब्बार अंसारी , अब्दुल गनी सुलेमान मुर्मू आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

बांसलोय नदी से मिली देवी लोलिता की प्राचीनतम मूर्ति राज्य संग्रहालय का बढ़ाएगी शोभा

एनपीटी ब्यूरो

पाकुड़ (झा०खंड), बीते 14 मई 2024 को महेशपुर के कुलबोना गांव में बांसलोय नदी से बालु उठाव के क्रम में अचानक कौतुहल का केन्द्र बन गया था, जब मजदूरों को काले पत्थर की एक प्राचीन मुर्ति मिली थी। मुर्ति को प्रशासन ने तत्काल सुरक्षित रूप से जिला कोषागार, पाकुड़ में रखा। मुर्ति की पहचान अग्नि पुराण में वर्णित भगवान शिव की पत्नी लोलिता देवी के रूप में की गई है। यह मुर्ति क्लोरिटाइड फाइलाइट से बनाई गई है।

अधीक्षक पुरातत्वविद् (एएसआई, रांची सर्किल) के निर्देशानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रांची सर्किल की एक टीम, जिसमें डॉ. नीरज कुमार मिश्रा, सहायक अधीक्षक

पुरातत्वविद् महावीर ब्रम्हचारी, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1, पुरातत्व निदेशालय, झारखण्ड राज्य के अधिकारी मनोज कुमार शामिल थे। संयुक्त रूप से 4 फरवरी 2024 को ग्राम-कुलबोना, ब्लॉक- महेशपुर जिला- पाकुड़ में बासलोई नदी से प्राप्त देवी ललिता की मूर्ति का निरीक्षण किया। जिसे अब राज्य संग्रहालय, होटवार, रांची में प्रदर्शित करने के लिए कोषागार, पाकुड़ से स्कॉट कर आज ले जाया गया। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि महेशपुर प्रखण्ड के साथ- साथ पूरे पाकुड़ जिला के लिए यह गौरव का क्षण है, क्योंकि पूरे झारखण्ड में इस तरह का स्थापत्य कला की यह पहली मुर्ति पाई गई है।

जमशेदपुर में पहली बार स्काईडाइविंग फेस्टिवल शुरू, 23 फरवरी तक चलेगा महोत्सव

रांची। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने सोनारी हवाईअड्डे पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। झारखंड में पहली बार स्काईडाइविंग का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड पर्यटन विभाग के तत्वावधान में आठ दिवसीय स्काईडाइविंग महोत्सव का शुभारंभ रविवार को जमशेदपुर में हुआ। पहले दिन कम से कम नौ उत्साही प्रतिभागियों ने 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काईडाइविंग की। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने सोनारी हवाईअड्डे पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्काईडाइविंग एक रोमांचक खेल या गतिविधि है जिसमें व्यक्ति विमान से कूदता है और पैराशूट की सहायता से सुरक्षित लैंडिंग से पहले हवा में कलाबाजी करता है।

मंत्री कुमार ने कहा, हम राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और यह आयोजन उसी का एक हिस्सा है। झारखंड में पहली बार स्काईडाइविंग का आयोजन किया जा रहा है।

अवैध लॉटरी कारोबार समेत नशीली पदार्थ की विक्रय पर

प्रतिबंध लगाया जा सकता है या फिर उम्मीद से कम

एनपीटी ब्यूरो

पाकुड़ मुफरिसल थाना क्षेत्र के कई पंचायत में व्यापक रूप से नशीली पदार्थ, अवैध लॉटरी अन्य की खुलेआम विक्रय हो रही है। मगर स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवियों के द्वारा असमाजिक तत्वों द्वारा खुलेआम ऐसे हरकतें व गतिविधियों को बढ़ावा देने की इश्यू को रोकने की दिशा में कोई ठोस कदम या फिर सकारात्मक पहल नहीं करने के कारण असमाजिक तत्वों के मनोबल बढ़ा हुआ है। यदि गौर करें तो स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवियों को अवैध लॉटरी, नशीली पदार्थ की विक्रय करने वाले असमाजिक तत्वों के साथ चाय दुकानों/स्टॉलों अन्य में चाय की चुस्कियां लेते हुए असमाजिक तत्वों द्वारा समाज में व्याप्त कैसर जैसी अवैध लॉटरी, नशीली पदार्थ की खुलेआम गलत हरकतें व गतिविधियों को फैलाने



की रोकथाम को नजरअंदाज कर मुस्कराने की देखावा को बढ़ावा देने में सहायक साबित हो रहा है। पाकुड़ रेलवे लाइन के पूर्वी क्षेत्रों में अवस्थित कई पंचायतों की तो खासताहाल है, अगर जरा सी भी विरोध करें तो तु-तु, मैं- मैं शुरू हो जाता है और फिर गाली-गलौज की नौबत तक आ जाती है। बाहरेहाल जो भी हो स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि के द्वारा सख्ती न बरतना कहीं न कहीं निजी स्वार्थ के साथ वोट बैंक की इश्यू को दशाता है। जो समाज में व्याप्त कैसर जैसी अवैध लॉटरी कारोबार

सह- नशीली पदार्थ का विक्रय खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए किया जाना सवालिया निशान लगाने की इश्यू को दशाता है। वही नगर थाना क्षेत्र से लेकर हिरणपुर तक में भी एक सक्रिय लॉटरी माफिया आमजनों के द्वारा दो वक्त की रोजी रोटी के लिए कमाकर परीवार की पेट भरने वाले साधारण व्यक्तियों की जेब से सपनों की बौछार करते हुए कागज के टुकड़ों में हजारों निजी स्वार्थ के साथ वोट बैंक की इश्यू को दशाता है। जो समाज में पैसा एंठकर मालामाल हो रहे हैं। और

अन्ततः साधारण व्यक्ति अप्रयोजनीय सपने की चक्कर में जो दो पैसे परिवार की पेट भरने के लिए पसीना बहाते हुए परिश्रम के बदले मिले पैसे को जेब से आसानी से निकल कर अवैध लॉटरी माफियाओं के धंधे में इजाफा कराते हुए अपने आप को असहजता महसूस किया करते हैं। जिसपर गौर करने की जरूरत है। यदि ऐसी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाया तो वह दिन दूर नहीं जब कुछ माफिया के पास बेतहाशा धन अर्जित होगा और बदले में लाखों गरीब मजदूर और गरीबी आलाम में मुब्तला होता हुआ नजर आयेगा और पछतावा के सेवा कुछ हासिल नहीं होगा। वही समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हाजीकुल आलम ने अवैध लॉटरी विक्रय को ले पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अवैध लॉटरी विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यक कारवाई करने की मांग की है।

70 बीघा जमीन में काटी जा रही अवैध कालोनी को प्राधिकरण ने किया ध्वस्तिकरण



एनपीटी ब्यूरो/सुखपाल सिंह

गाजियाबाद। जोन एक में 70 बीघा जमीन में अवैध कॉलोनी को प्राधिकरण ने ध्वस्तिकरण किया गया। इस मौके पर एई आदि मौके पर थे। अवैध कॉलोनी काट रहे सुनील चौधरी आदि वहां से भाग खड़े हुए।

निगम की भूमि कब्जा कर बेचने वाले नौ लोगों पर होगा मुकदमा

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

गाजियाबाद। महापौर सुनीता दयाल ने सोमवार को नंदग्राम स्थित नगर निगम की भूमि का निरीक्षण किया। जांच के दौरान निगम की भूमि से कब्जा हटवाने का आदेश देने के साथ ही उन्होंने धोखाधड़ी से निगम की जमीन बेचने वाले मुकेश त्यागी, नवीन त्यागी, विकास त्यागी, अवधेश त्यागी, नंदू त्यागी, विनोद त्यागी, आरडी त्यागी, शिव कुमार त्यागी, धर्मपाल प्रजापति पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए

महापौर ने बताया कि संगम विहार, मरियम नगर और नंदग्राम में 100 बीघा से भी अधिक भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके प्लॉट काट दिया। जिसकी सूचना के बाद वार्ड छह की पार्श्व छाया त्यागी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ



उन्होंने मौके पर जांच की। जांच में खसरा नंबर 207, 208, 172, 142, 167, 98, 95, 1082, 87, 88, 113, 117, 60 व 74 की अधिकांश भूमि पर प्लॉट काटकर बेच दिया गया था। इस भूमि पर मकान भी बन गए थे। कुछ भूमि खाली भी पड़ी थी, जिसमें उन्होंने सब्जी उगा रखी थी कुछ भूमि को खेती के लिए

कियाए पर दे दिया गया था। नए बने मकान मालिकों को बुलाकर जानकारी ली, तो पाया कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है।

ऐसे में सात लोगों को चिह्नित करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि निगम के पांच सौ करोड़ की सौ बीघे से अधिक भूमि पर कब्जा हो चुका

है। निरीक्षण के दौरान भूमि बेचने वाले नौ लोगों का नाम प्रकाश में आया। जिस पर नंदग्राम थाना प्रभारी को मौके पर बुलाकर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।

-पहले भी निगम कर चुका है कार्रवाई-महापौर ने बताया कि नगर निगम ने अपनी भूमि को खाली कराने के लिए मरियम नगर में 500 गज पर बने मकान को सील किया था। इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन जांच के दौरान उक्त भवन में नगर निगम के लिखे नाम को छिपाकर हॉस्टल का संचालन होता मिला। जिस पर हॉस्टल मालिक ईश्वर त्यागी, आयुव को हॉस्टल खाली कराने के साथ ही निगम के अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया गया।

ट्रेनें घटीं, यात्री बढ़े...स्टेशन पर मारामारी



नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

गाजियाबाद। गाजियाबाद से होकर गुजरने वाले ट्रेनों की संख्या कम हो गई है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रद्द चल रही हैं। दूसरी ओर, महाकुंभ की वजह से यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। नतीजा यह है कि स्टेशन पर मारामारी के हालात बने हुए हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ से हुए हादसे के बाद माना जा रहा था कि रेलवे की ओर से बड़े कदम उठाए। व्यवस्था सुधार के लिए कुछ उपाय किए भी गए हैं लेकिन

भीड़ के आगे यह नाकाफी है। प्लेटफार्म पर रस्सी बांध दी गई है। आलम यह है कि ट्रेन नजर आते ही यात्री उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। जो प्लेटफार्म से नहीं चढ़ पाते, वे नीचे उतरते हैं और पटरी पर चलकर दूसरी ओर सवार होने का प्रयास करते हैं। यह खतरनाक है लेकिन कोई इन्हें रोक नहीं रहा। स्टेशन पर रोज लगभग एक लाख लोग पहुंच रहे हैं। आम दिनों में यह संख्या 80 से 90 हजार रहती है।

कोई रस्सी से ऊपर से गया तो कोई नीचे से सोमवार दोपहर को दिल्ली से लखनऊ जाने वाली गोमती एक्सप्रेस जैसे ही स्टेशन पर पहुंची, वैसे ही यात्री उसमें सवार होने के लिए दौड़ पड़े। धक्का-मुक्की के हालात बन गए। प्लेटफार्म पर लगाई गई रस्सी को ट्रेन आते



ही आरपीएफ के जवान हटा देते हैं लेकिन भीड़ इतनी थी कि इसका मौका ही नहीं मिला। कोई रस्सी कूदकर आगे निकला तो कोई रस्सी के नीचे से। बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफार्म से उतर गए। ये पटरियों पर होकर ट्रेन की दूसरी तरफ से सवार हुए।

रविवार की रात 11 बजे बनारस एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर पहुंची। सैंकड़ों यात्री इंतजार में खड़े थे। ट्रेन आते ही शोर मच गया। लोग ट्रेन में सवार होने के लिए दौड़ पड़े। कई तो कोच की खिड़की से ही घुस गए। जिन लोगों ने रिजर्वेशन नहीं कराया था, वे भी कोच में घुस गए। इस पर कहासुनी हो गई। काफी देर हंगामा चला लेकिन पुलिस की ओर से कोई नहीं आया। वाराणसी जा रहे कपिल शर्मा ने बताया कि जिन

लोगों के टिकट कंफर्म नहीं हो पाए हैं, वे भी महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन में सवार हो रहे हैं। धक्का-मुक्की मत करो

आरपीएफ की ओर स्टेशन पर पैदल मार्च किया गया। लाउडस्पीकर पर यात्रियों से अपील की गई कि वे धक्का-मुक्की न करें। उनसे यह भी कहा गया कि अगर एक ट्रेन में सीट न मिले तो दूसरी का इंतजाम करें। महाकुंभ के लिए रेलवे की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर बाहर से भी कर्मचारी बुलाए हैं। आरपीएफ के 15 जवान लगाए गए हैं, जो प्लेटफार्म एक से तीन तक 12-12 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं।

- यशवंत सिंह सलूजा, निरीक्षक आरपीएफ

हैबीटेट हब सेंटर सील करने पहुंची नगर निगम टीम तो जमा कराए 32 लाख

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

साहिबाबाद। नगर निगम की टीम कर वसूली अभियान के तहत सोमवार को इंदिरापुरम के रॉयल टावर व हैबीटेट सेंटर पहुंची। हैबीटेट सेंटर पर निगम का 32 लाख बकाया है। टीम जब सील करने पहुंची तो प्रबंधन ने 32 लाख रुपये जमा कराए और अन्य राशि जमा कराने की मोहलत ली। इस दौरान नगर निगम की टीम इंदिरापुरम के रॉयल टावर में

सीलिंग की कार्रवाई की। गृह कर वसूली अभियान के तहत नगर निगम की टीम सुबह आठ बजे से ही कार्य में जुट जाती है। सोमवार दोपहर टीम वैभवखंड स्थित हैबीटेट सेंटर पहुंची। कर जमा न करने पर जब मॉल के कार्यालय को सील किया जाने लगा तो प्रबंधन की ओर से पैसे जमा कराए गए। इस दौरान यहां स्थित कई दुकानों पर निगम की टीम ने नोटिस भी चस्पा किया। निगम लगातार शहर

वासियों को अपना बकाया हाउस टैक्स जमा करने के लिए अपील कर रहा है। बड़े बकायेदारों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। हैबीटेट सेंटर पर कार्रवाई करने पहुंची टीम में वसुंधरा जोन के प्रभारी सुनील राय ने बताया कि नगर आयुक्त के आदेश पर टीम हर दिन अभियान चलाए हुए है और कर जमा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

मेरठ कॉलेज में पेड़ काटने पर भड़के छात्र, धक्कामुक्की और खींचतान में दरोगा जख्मी, एक घंटे तक चला हंगामा

मेरठ। मेरठ कॉलेज प्रबंधन ने पिछले दिनों हरे पेड़ कटवा दिए थे। विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को छात्र एकत्र हुए और हंगामा करते हुए पुतला फूंका।

हरे पेड़ कटवाकर लकड़ी बेचने का आरोप लगाते हुए मेरठ कॉलेज के छात्रों ने सोमवार दोपहर 12 बजे कॉलेज प्रशासन की सांकेतिक शक्यता निकाली। पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों में झड़प हुई। इसमें एक दरोगा जख्मी हो गया। हंगामे के बीच छात्रों ने पुतला फूंक दिया। करीब एक घंटे तक कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ।

मेरठ कॉलेज प्रबंधन ने पिछले दिनों हरे पेड़ कटवा दिए थे। इसके विरोध में छात्र आंदोलनरत हैं। सोमवार को विद्यार्थी कॉलेज की पार्किंग में छात्र नेता विजित तालियान के साथ एकत्र हुए। कॉलेज प्रबंधन द्वारा गठित की गई जांच समिति के निर्धारित समय के बाद कोई जवाब नहीं देने पर नाराजगी जताई गई। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन की सांकेतिक शक्यता निकाली। पार्किंग से प्राचार्य दफ्तर से होते हुए पूरे कॉलेज में यात्रा निकाली गई। इसी दौरान पुलिस पहुंच गई और छात्रों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को धकेलते हुए वे आगे बढ़ गए। प्रबंध समिति के सचिव विवेक गर्ग के दफ्तर के बाहर छात्र पुतला जलाने लगे। पुलिस ने पुतला छीनने व छात्रों को रोकने का प्रयास किया। यहां छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई। धक्का-मुक्की और हंगामे के बीच छात्रों ने पुतले में आग लगा दी। विजित तालियान ने बताया कि छात्र हरे व फलदार पेड़ कटवाकर लकड़ी माफिया को बेचने का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान प्रियांशु मलिक, तरुण सहरावत, दक्ष चौधरी, शानू, मनीष, कुशल आदि मौजूद रहे।

100 से ज्यादा पेड़ कटवाने का आरोप-छात्र नेता विजित तालियान का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने 100 से ज्यादा हरे पेड़ वन विभाग की अनुमति के बिना कटवा दिए। इसमें आम, शीशम और शहतूत आदि के पेड़ थे। आरडी और ऑडी हॉस्टल की दीवार रातोंरात तोड़कर पेड़ कटवाए गए और फिर रात में ही दीवार चिनवा दी गई। इसके बाद बीएनएम हॉस्टल के पेड़ कटवाए गए।

ट्रकों में लादकर ले गए लकड़ी, क्लिप हैं मौजूद-उनके पास कुछ वीडियो क्लिप भी हैं, जिनमें चोरी छिपे पेड़ काटकर ट्रकों में ले जाया जा रहा है। वह लगातार कॉलेज प्रबंधन से इस संबंध में जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।

सीओ कैट सुभाष सिंह ने बताया कि पुलिस ने छात्रों को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वह नहीं माने। पुलिस के साथ कोई धक्का-मुक्की या अभद्रता नहीं हुई। कॉलेज प्रबंधन तहरीर देगा तो रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जाएगी।

तमंचे और पिस्टल की दुकान लगाए चारपाई पर बैठा किशोर... रील बनाकर डाल दी इंस्टाग्राम पर

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

मेरठ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी सलारपुर गांव रहने वाला है। पुलिस ने उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है, जबकि आरोपी फरार है। सोशल मीडिया पर सात तमंचे और एक पिस्टल के साथ युवक का फोटो

वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में चारपाई पर बैठा नाबालिग हाथ में पिस्टल लिए हुए है। 7 तमंचे उसके आगे गोद में और आगे रखे हुए हैं। जांच पड़ताल में फोटो गंगानगर क्षेत्र के सलारपुर गांव का होना सामने आया है। फोटो को एक गाने के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टेटस पर लगाया गया है। डिफाल्टर अंडर स्कोर शाबाज



अंडर स्कोर 001 पर फोटो अपलोड किया गया। वायरल वीडियो में तमंचे के साथ बैठे नाबालिग के चेहरे को इमोजी से छुपाया गया है।

इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि जांच में आरोपी सलारपुर गांव रहने वाला सामने आया है। फोटो यहीं खींचा है या कहीं और, ये जांच की जा रही है। आरोपी के घर-परिवार का भी पता चल

गया है। उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है, जबकि आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी है। घटना में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं

इस मामले को लेकर अधिकारियों ने तुरंत सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

मोतियाबिंद बच्चों पर

चोट, आनुवांशिक और गर्भ में बीमारी से हो सकती समस्या

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

गाजियाबाद। एमएमजी अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेंद्र कुमार का कहना है कि वंशानुगत (एक से ज्यादा अनुवांशिक या क्रोमोसोमल विकार), मेटाबोलिज्म के विकार (गैलैक्टोसीमिया) या गर्भ में रहते हुए किसी से मिले हुए संक्रमण (रुबेला) या गर्भावस्था के दौरान मां की किसी अन्य बीमारी के कारण हो रहे हैं। चोट लगने, आनुवांशिक और गर्भावस्था के दौरान बच्चे में संक्रमण या किसी तरह की बीमारी का दुष्प्रभाव बच्चों की आंखों में मोतियाबिंद के रूप में हो रहा है। एमएमजी अस्पताल में दो महीने में आठ से 11 वर्ष के 10 बच्चों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। इनमें से चार बच्चों की आंखों में चोट लगने, तीन बच्चों में आनुवांशिक (माता-पिता दोनों को मोतियाबिंद) मोतियाबिंद की पुष्टि हुई थी एमएमजी अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेंद्र कुमार का कहना है कि वंशानुगत (एक से ज्यादा अनुवांशिक या क्रोमोसोमल विकार),



मेटाबोलिज्म के विकार (गैलैक्टोसीमिया) या गर्भ में रहते हुए किसी से मिले हुए संक्रमण (रुबेला) या गर्भावस्था के दौरान मां की किसी अन्य बीमारी के कारण हो रहे हैं। खेलते समय बच्चे की आंख में चोट लगने, रेडिएशन के संपर्क में आने से मोतियाबिंद हो जाता है। डॉ. नरेंद्र का कहना है कि बच्चों में मोतियाबिंद के कई अन्य कारण भी होते हैं।

बच्चों में मोतियाबिंद का कारण ट्रॉमेटिक मोतियाबिंद: खेलते समय या किसी खेल के दौरान बच्चे को लगी

कोई भी चोट मोतियाबिंद का कारण बन सकती है। अगर चोट लगने के समय नहीं तो कुछ वर्षों के बाद मोतियाबिंद हो सकता है।

जन्मजात मोतियाबिंद: जन्म के समय या बचपन में भी बच्चों को मोतियाबिंद होने की संभावना होती है। यह परेशानी एक साथ दोनों आंखों में हो सकती है। लेकिन, इस मोतियाबिंद को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती और इससे देखने में भी कोई परेशानी नहीं होती। रेडिएशन मोतियाबिंद : बच्चे के रेडिएशन के

बच्चों में मोतियाबिंद के लक्षण

दृष्टि का कमजोर होना: इससे बच्चे को लोगों और अन्य वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है

भैंगापन: दोनों आंखों का अलग-अलग दिशाओं में इशारा करने के लक्षण होने पर भी मोतियाबिंद होता है।

तीव्र नेत्र गति: निस्तागमुस की परेशानी होने पर आंखों की गति को तेज कर देता है जैसे पलकें झपकाना और हिलना।

रंगों का फीका दिखना, धुंधली नजर, आंखों को रोशनी बहुत तेज लगना, दृष्टि कम हो जाना

संपर्क में आने के कारण होने वाले मोतियाबिंद को रेडिएशन मोतियाबिंद के रूप में जाना जाता है। माध्यमिक मोतियाबिंद: डायबिटीज या किसी अन्य बीमारी के कारण होने वाले मोतियाबिंद को सेकेंडरी मोतियाबिंद माना जाता है, साथ ही कुछ दवाओं और स्टेरॉयड के उपयोग से भी ये समस्याएं हो सकती हैं।